नई दिल्ली ■ शनिवार 04 अप्रैल 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 14 ■ अंक 06 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 सीबीआई की सीमाएं और सवाल | 07 सूर्यवंशी के सामने होगी गुजरात के तेज गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा | लीसा मिश्रा ने 6 महीने तक आवाज़ खोने के बारे में किया खुलासा 08

ईरान ने अमेरिका के एफ-35 समेत दो विमानों को मार गिराया

तेहरान। पश्चिम एशिया में 35 दिनों से जारी युद्ध के बीच ईरान ने अपने मध्य हवाई क्षेत्र में अमेरिका के एफ-35 समेत दो लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया है। इसके पहले भी ईरानी सेना ने एक एफ-35 विमान को मार गिराया था।

ईरान के प्रेसईडी और तसनीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका के इन दो विमानों को मार गिराने का दावा ऐसे समय में किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने की बात कही थी। हालांकि, इस दावे पर अभी तक अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आईआरजीसी के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक अमेरिका के दो एफ-35, एक एफ-18, दो एफ-16 और चार एफ-15 विमानों को मार गिराया गया है। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि उसके नए विकसित और आधुनिक हवाई सुरक्षा तंत्र ने मध्य ईरान में एक स्टेल्थ एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। हमले में विमान के पूरी तरह से बिखर जाने के कारण पायलट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इससे पहले आईआरजीसी ने घोषणा की थी कि क़ेश्म द्वीप के दक्षिण में हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा एक और आधुनिक दुश्मन लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया था। वह आधुनिक विमान हेंगम और केश्म द्वीपों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फ़ारस की खाड़ी में समा गया। विमान को मार गिराने की यह घटना वाशिंगटन की हालिया बयानबाजी का सीधा जवाब थी।

आईआरजीसी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दावा किया था कि अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के हवाई सुरक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया है। आईआरजीसी के बयान में कहा गया है कि उनकी हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से नष्ट होने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के झूठे दावे के बाद कुछ ही देर पहले केश्म द्वीप के दक्षिण में नौसेना के आधुनिक हवाई सुरक्षा तंत्र द्वारा एक आधुनिक दुश्मन लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया।

इसके पूर्व आईआरजीसी ने 11 मार्च को ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वायु सेना के एक एफ-35 विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया था। हालांकि, अमेरिकी मीडिया ने बाद में इसकी पुष्टि की थी। हालांकि पेंटागन लगातार इन भारी नुकसानों को छिपाने की कोशिश करता रहा है और इन विमानों के गिरने की घटनाओं को 'गलती से हुई गोलीबारी' या 'दुर्घटना' के रूप में पेश करता रहा है।

ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम और नौसैनिक उपकरणों को किया नष्ट

तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर मौजूद रडार सिस्टम, नौसैनिक उपकरणों एवं हवाई अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर नष्ट कर दिया है। हालांकि, इन दावों की अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है। ईरान के सरकारी समाचार मीडिया संगठन प्रेसईडी ने आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग के हवाले से बताया कि ईरानी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में फिलिस्तीनी इलाकों में मौजूद अमेरिकी आतंकवादियों के रडार सिस्टम और नौसैनिक उपकरणों को पूरी तरह तबाह कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में रोड शो किया, राजग को वोट देने की अपील की

पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पुडुचेरी में रोड शो कर 09 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से दोबारा अवसर देने की अपील की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए इसे 'शानदार' बताया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की जनता ने 'बीईएसटी पुडुचेरी' के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को पुनः चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को भी सराहा। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व में पुडुचेरी ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है।

उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, रोजगार सृजन, रिक्त पदों को भरने और किसानों व युवाओं के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम ई-बस सेवा के तहत शुरू की गई ई-बसों से परिवहन अधिक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल हुआ है। उन्होंने एनएच-32 के एक हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर, एनएच-332ए के 14 किमी हिस्से के उन्नयन और पुडुचेरी-पुंडियानकुप्पम सेक्शन के चार लेन निर्माण से बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र किया। साथ ही, मरक्कानम-पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और माहे स्टेशन के अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प का भी उल्लेख किया।

उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि एनआईटी कराईकल में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक, गंगा हॉस्टल, जिपमर के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र का आधुनिकीकरण और पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नए बुनियादी ढांचे से स्थानीय जरूरतों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी लाभ मिलेगा। आर्थिक विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने करासूर-सेदारापेट औद्योगिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण परियोजना बताया, जहां फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा आने वाले समय में अनुसंधान एवं विकास (आरएडंडी) केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़कों, हेरिटेज टाउन, मैंग्रोव संरक्षण और जल आपूर्ति सुधार जैसी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, जिन्हें 'डबल इंजन' सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि उनके पास पुडुचेरी के विकास के लिए कोई दृष्टि नहीं है और वे इसे 'एटीएम' की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने 'डब्ल्यूईएके पुडुचेरी' की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अर्थ है– डब्ल्यू का अर्थ सबसे खराब शासन। ई का अर्थ विकास का अंत, ए का अर्थ जनता के खिलाफ और के का अर्थ अर्थव्यवस्था को नुकसान से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पुडुचेरी को मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता से गठबंधन को समर्थन देने की अपील की।

मप्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधान सभा सदस्यता खत्म

भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया से निर्वाचित सदस्य राजेन्द्र भारती के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह (पीसी एक्ट) सीबीआई 09 (सांसद/विधायक मामले) राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक एससी-06-2025 पर पारित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2026 द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप तीन वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस कारण उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत राजेन्द्र भारती उक्त तिथि 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं। अतएव मध्य प्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।

राजधानी में फिर बढ़ा प्रदूषण 266 एक्यूआई दर्ज

नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से बारिश और हवा के चलते राजधानी की साफ आबोहवा में एक बार फिर प्रदूषण घुल गया है। शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया, जोकि खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार राजधानी में धूर भरी आंधी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।

इस संबंध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उपसमिति ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और फिलहाल ग्रैप एक की पाबंदियां नहीं लागू करने का फैसला किया है। आयोग ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली में आज दोपहर 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। कल दिल्ली का औसत एक्यूआई 194 था, जो आज 266 तक बढ़ गया। इस तेज बढ़ोतरी का मुख्य कारण सुबह के समय आए धूल भरी आंधी को माना गया। उप-समिति ने शाम 4:15 बजे बैठक बुलाकर स्थिति का विश्लेषण किया। मौसम विभाग और आईआईटीएम की पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल रात हल्की बारिश की संभावना है। जिससे एक्यूआई में सुधार होने की उम्मीद है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी ने बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल स्टेज -I ग्रैप लागू करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' भारत के समुद्री बेड़े में शामिल

नई दिल्ली। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़े में एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को शामिल कर लिया गया। विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों कमीशनिंग हुई। तारागिरी को ऐसे समय में शामिल किया गया है, जब भारत के पूर्वी समुद्री तट का रणनीतिक और समुद्री महत्व लगातार बढ़ रहा है। तारागिरी के नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता और ऑपरेशनल पहुंच में काफी बढ़ोतरी होगी।

प्रोजेक्ट 17ए वर्ग का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट 'तारागिरी' केवल एक जहाज नहीं है, बल्कि यह 'मेक इन इंडिया' की भावना और हमारे स्वदेशी शिपयार्ड की इंजीनियरिंग क्षमताओं का 6,670 टन का अवतार है। मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित यह फ्रिगेट पहले के डिजाइनों की तुलना में एक पीढ़ी की छलांग है। 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह जहाज घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को उजागर करता है, जो अब 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में फैला हुआ है। संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र से संचालित तारागिरी को 'उच्च गति-उच्च धीरज' बहुमुखी प्रतिभा और बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।जहाज का हथियार सूट विश्वस्तरीय है, जिसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध सूट है।

इन प्रणालियों को अत्याधुनिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से मूल रूप से एकीकृत किया गया है, जिससे चालक दल सटीकता के साथ खतरों का जवाब दे सकता है। स्टेल्थ फ्रिगेट का लचीला मिशन प्रोफाइल इसे उच्च-तीव्रता वाले मुकाबले से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत तक के लिए आदर्श बनाता है। भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, एकजुट, विश्वसनीय आत्मनिर्भर बल के तौर पर लगातार बढ़ रही है। तारागिरी उभरते हुए समुद्री पावर और देश की नीली सीमाओं के मजबूत संरक्षक के रूप में अच्छे भविष्य के लिए तैयार है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी नौसेना चाहे फारस की खाड़ी हो या मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह निकासी ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता देना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नौसेना की ताकत, मूल्यों और प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी।

बाराही मेला-2026 में उमड़ा जनसैलाब

शेख चिल्ली ने बेटी बचाओ विषय पर दिया मार्मिक संदेश

नोएडा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सूरजपुर में आयोजित हो रहा चर्चित बाराही मेला-2026 में श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं एवं दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा मेला परिसर जनसैलाब में तब्दील हो गया। दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने परिवार सहित मेले में पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भरपूर आनंद लिया।

इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रसिद्ध कलाकार हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली ने सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक मार्मिक संदेश देते हुए "बेटी बचाओ" विषय पर आधारित भजन-"मत मरवाओ भाई, यह बेटी है प्यारी..."प्रस्तुत किया। इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को भावुक कर दिया, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी दिया। उपस्थित जनसमूह ने इस प्रस्तुति की सराहना करते हुए कलाकार का जोरदार तालियों से स्वागत किया। इसके अतिरिक्त राज चौधरी इवेंट हरियाणवी डांस ग्रुप के कलाकारों ने अपने शानदार नृत्य और गीत-संगीत की प्रस्तुतियों से मंच पर ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। पारंपरिक हरियाणवी लोकनृत्य और आधुनिक शैली के संगम ने दर्शकों को देर तक बांधे रखा और कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। मेले में उमड़ी अपार भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि बाराही मेला क्षेत्र की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।यहां मेले में लगे झूले, दुकानें, खानपान स्टॉल और अन्य आकर्षणों ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं मेले में स्थापित प्राचीनकालीन चौपाल और बड़ी खाट, विशाल हुक्का, बड़ी रई, पीढ़ा व बैलगाड़ी जैसी पारंपरिक कृषि वस्तुएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनीं हुई है। राजस्थान से आए कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य, बीन पार्टी और नगाड़ा पार्टी की प्रस्तुति दी जिसमें ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखी। शिव मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए कठपुतली शो, नट कला, मौत का कुआं, सर्कस, जादूगर शो और झूले लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के कारण सरोवर में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी कफी वृद्धि हुई है।

घर का ताला तोड़कर जेवरात और सात लाख की नकदी चोरी

दादरी। नई आबादी मोहल्ले में फैजान मदरसे के पास बंद घर से चोर सोने-चांदी के जेवरात समेत सात लाख रुपये और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के तीन दिन बाद दादरी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस चोरों की तलाश में लगी है। पीड़ित शाहिद ने बताया कि घर में शादी के लिए बनाए जेवरात और अलमारी में नकदी रखी थी। चोरी के वक्त परिजन बेटी के ससुराल गए थे कि तभी 31 मार्च की रात को चोरी हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। तीन दिन बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसीपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कि दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आवंटित दुकानों को खाली करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

ग्रेटर नोएडा। दादरी के रेलवे रोड पर आवंटित दुकानें खाली कराने के नगर पालिका के नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अदालत ने नगर पालिका की कार्रवाई को अनुचित ठहराया। कोर्ट के इस फैसले ने प्रभावित दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार, भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान विस्थापित होकर आए पंजाबी परिवार दादरी में बस गए थे। आजीविका के लिए वे रेलवे रोड पर खोखे लगाकर व्यापार करते थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उन्हें बार-बार हटाया जाता था। इसके बाद साल 1990 में नगर पालिका ने उन्हें पक्की दुकानें आवंटित कीं। तभी से करीब 25 दुकानदार इन दुकानों में फल और सब्जी बेचते थे। हाल ही में नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी ने इन 25 दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। इसके अनुसार, 1 सितंबर 1990 को 33 वर्षों के लिए दुकानें आवंटित की गई थीं और अब उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए दुकानदारों को 15 दिनों के भीतर दुकानें खाली करने के आदेश दिए गए थे। दुकानदारों ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें अतिक्रमण हटाने के दौरान पुनर्वास के तहत दुकानें दी गईं थीं और उस समय किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने नोटिस को गलत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की, लेकिन नगर पालिका ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। तब प्रभावित दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 25 मार्च को नोटिस पर रोक लगा दी थी और मामले की आगली सुनवाई एक अप्रैल को करने को कहा था। इस सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

सेंचुरियन कप के लीग मैच में एपिक ब्लास्टर्स को मिली जीत

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित सेंचुरियन क्रिकेट मैदान पर चल रहे सेंचुरियन कप सीजन-15 के लीग मैच में एपिक ब्लास्टर्स ने बिसंस को 27 रन से पराजित किया। नितिन उप्पल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी एपिक ब्लास्टर्स ने टी-20 मुकाबले में सात विकेट के नुकसान पर 183 रन का स्कोर खड़ा किया। नितिन उप्पल ने 74 रन की पारी खेली। लक्ष्य को पीछा करने उतरी बिसंस की टीम आठ विकेट के नुकसान पर 156 रन ही बना सकी।

लीग मैच में 193 रन से जीती मद्रास सीसी

ग्रेटर नोएडा। इंपीरियल क्रिकेट मैदान पर चल रहे दूसरे राधे श्याम शर्मा मेमोरियल इनविटेशन प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में मद्रास सीसी ने यंगस्टर सीसी को 193 रन से पराजित किया। अनी मैन ऑफ द मैच रहे। मद्रास सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर के मुकाबले में नौ विकेट के नुकसान पर 340 रन का स्कोर खड़ा किया। अनी ने 101 रन और सूरज सिंह ने 94 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से शिवम ने चार विकेट हासिल किए। दूसरी पारी में यंगस्टर सीसी की टीम 21.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 147 रन ही बना सकी। मद्रास सीसी की ओर से राहुल ए चौधरी ने तीन विकेट हासिल किए।

विभिन्न सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत

नोएडा। नोएडा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की मौत हो गयी है। इनमें दो लोगों की मौत नोएडा में सड़क हादसों में हुई, जबकि तीसरे की मृत्यु नोएडा में उपचार के समय हुई। पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये।

थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि बीती रात को वीरेंद्र शर्मा पुत्र बसंत लाल शर्मा उम्र 48 वर्ष तिलपता गोल चक्कर के पास पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक कंटेनर के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि अंकित तिवारी उम्र 28 वर्ष थाना बिसरख क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में बीती रात को गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना बिसरख पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नॉलेज पार्क के प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल जाने आलम पुत्र सलीम को उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नव विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति पर गंभीर आरोप

नोएडा। नोएडा के थाना सेक्टर 63 क्षेत्र के बाजितपुर गांव में रहने वाली एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अमित काकरान ने बताया कि पूजा पत्नी ब्रिज किशोर उम्र 22 वर्ष की 2 वर्ष पूर्व ब्रिज किशोर से शादी हुई थी। वह मौजूदा समय में वाजिदपुर गांव में रह रही थी, जबकि वह मूल रूप से कन्नौज जनपद की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि बीती रात को पूजा अपने घर पर मूर्छित अवस्था में मिली। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। डॉक्टरों ने बिसरा प्रिजर्व किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका के परिजनों ने उसके पति पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीमा हैदर ने अपने बेटे का नाम रखा भारत

नोएडा। पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर फरवरी ,2026 में छठी बार मां बनी थीं। सीमा और उनके पति सचिन ने बेटे का नामकरण किया। कपल ने बेटे का नाम 'भारत' रखा है जिसे जानने के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को मिर्च जरूर लगेगी। नामकरण समारोह नोएडा के रबुपुरा स्थित उनके निवास पर आयोजित किया गया। इस दौरान सीमा ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत सुंदर है और उन्हें हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है।

बेटे के नामकरण को लेकर सीमा हैदर ने कहा कि 'हिंदू धर्म में जब घर में बेटा होता है तो नामकरण किया जाता है। यह दूसरा कुआं पूजन है, इससे पहले जब मीरा हुई थी तब कराया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी खूबसूरती यहां दिखती है। छोटे-छोटे त्योहार प्यार बढ़ाते हैं। मैं बहुत खुश हूं और मुझे कभी पछतावा नहीं होता। मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदू हूं।'बेटे का नाम भारत रखने के पीछे क्या वजह थी, इसपर सीमा बताती हैं कि 'पंडित ने जब नाम निकाला तो वह 'भ' अक्षर से आया तो हमने सोचा कि भारत से सुंदर नाम कोई हो ही नहीं सकता तो हमने रख लिया। उन्होंने आगे कहा कि 'भारत को सपोर्ट करना उन्हें अच्छा लगता है। हर मैच में वह भगवान से भारत की जीत की प्रार्थना करती हैं। जब भारत जीतता है, तो उन्हें गर्व और खुशी महसूस होती है।

उनके अनुसार, जीत के बाद पूरा परिवार मिलकर जश्न मनाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। हर जाति और धर्म के लोग रबूपुरा में रहते हैं। मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। मुझे अपनी बहू मानते हैं।' सीमा साल 2023 में अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थीं । सीमा के पहले पति से चार बच्चे हैं। जबकि, सचिन से मिलने के बाद वह दो और बच्चों की मां बनी हैं। पाकिस्तानी नागरिक सीमा साल 2023 में अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थीं।

सचिन से सीमा की मुलाकात ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान हुई थी। इसके बाद सीमा जब यूपी आई तो सचिन ने उन्हें किराए के मकान में अपने साथ रखा। कपल यह भी दावा करता है कि दोनों ने 2023 में काठमांडू के एक मंदिर में शादी की थी। सीमा कई मौकों पर कह चुकी हैं कि अब हिंदुस्तान ही उनके लिए सब कुछ है और वह यहां पर ही रहना चाहती हैं।

यथार्थ हॉस्पिटल में रैपिड एआई तकनीक की शुरुआत

ग्रेटर नोएडा। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, ओमेगा-1 में रैपिड एआई तकनीक की शुरुआत की गई है। इस नई तकनीक के माध्यम से ब्रेन स्ट्रोक और न्यूरोवस्कुलर बीमारियों की पहचान अब पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक हो सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है, जिसमें दिमाग तक रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है या रक्त वाहिका फट जाती है। ऐसे में हर मिनट बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देरी से दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है।

रैपिड एआई तकनीक इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है, जो सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांचों का स्वतः विश्लेषण कर कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। यह तकनीक बड़ी रक्त वाहिकाओं में रुकावट, रक्त प्रवाह की स्थिति और दिमाग में हुए नुकसान का आकलन तेजी से करती है। रियल-टाइम अलर्ट के जरिए डॉक्टरों को तुरंत निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिससे इलाज में देरी कम होती है और मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार रैपिड एआई तीन मिनट से भी कम समय में विस्तृत और रंग-कोडेड रिपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है, जो पारंपरिक जांच प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज है। इससे उन महत्वपूर्ण क्षणों में सहायता मिलती है, जब हर मिनट में लाखों न्यूरॉन्स नष्ट हो सकते हैं।

सीओओ एवं फैसिलिटी डायरेक्टर डॉ. सुनील बलियान ने बताया कि यह तकनीक विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में जीवनरक्षक साबित होगी और मरीजों को समय पर सटीक इलाज उपलब्ध कराने में मदद करेगी। वहीं न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. सुमित गोयल ने कहा कि स्ट्रोक का इलाज समय पर निर्भर करता है और रैपिड एआई के जरिए स्कैन का त्वरित विश्लेषण कर सही समय पर उपचार शुरू किया जा सकता है, जिससे मृत्यु दर और विकलांगता में कमी लाई जा सकती है। हॉस्पिटल में पहले से उपलब्ध कैथ लैब, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ अब इस नई तकनीक के जुड़ने से मरीजों को और अधिक प्रभावी एवं त्वरित उपचार मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रैपिड एआई तकनीक न केवल बीमारी की पहचान को तेज करती है, बल्कि बचाए जा सकने वाले दिमागी ऊतक की पहचान कर उपचार की समय-सीमा को भी बढ़ाती है। इससे स्ट्रोक जैसे गंभीर मामलों में मरीजों के जीवन की रक्षा और बेहतर रिकवरी की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

गलगोटिया विश्वविद्यालय और सेल्सफोर्स की पहल छात्रों के लिए शुरू हुआ टैबलो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

ग्रेटर नोएडा। उच्च शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल को मजबूत करते हुए गलगोटिया विश्वविद्यालय ने सेल्सफोर्स के सहयोग से अपने परिसर में 'सेल्सफोर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस – टैबलो एआई डेटा लैब' की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन के क्षेत्र में इंडस्ट्री-रेडी बनाना है।

विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित इस लैब के माध्यम से छात्रों को एडवांस्ड एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस और एआई-सक्षम डेटा इंटरप्रिटेशन का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। साथ ही रियल-वर्ल्ड एप्लिकेशन पर आधारित प्रशिक्षण देकर उन्हें डेटा-ड्रिवन निर्णय लेने के लिए तैयार किया जाएगा। इस सहयोग के तहत छात्रों को इंडस्ट्री-अलाइन पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल लर्निंग मॉड्यूल्स और एंटरप्राइज-लेवल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप्स और गाइडेड लर्निंग पाथवे के जरिए शिक्षकों को भी नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा। गलगोटिया विश्वविद्यालय के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्रों को ऐसा शिक्षण वातावरण देना है, जो उन्हें सीधे उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ सके। उन्होंने कहा कि यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छात्रों को केवल तकनीकी टूल्स तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें डेटा को समझने, विश्लेषण करने और वास्तविक जीवन में उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान करेगा। यह सेंटर विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए उपयोगी होगा, जिससे डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई आधारित इनसाइट्स और डिजिटल निर्णय प्रणाली जैसे क्षेत्रों में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल विश्वविद्यालय की इंडस्ट्री इंटीग्रेशन और भविष्य-उन्मुख शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और छात्रों को तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दिल्ली में चरस तस्करी रैकेट का खुलासा

1.436 किलो मलाणा क्रीम के साथ दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों की अंतर-राज्यीय तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 1.436 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता की चरस (मलाणा क्रीम) बरामद की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई 'नशा मुक्त दिल्ली' अभियान के तहत की गई, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने बेहतरीन कार्य किया। बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह खेप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाना गांव से लाई गई थी और इसे मुंबई में पहुंचाया जाना था।

19 मार्च 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला ओम चंद उर्फ ओमु दिल्ली में चरस की सप्लाई कर रहा है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रॉबिन त्यागी के नेतृत्व में और एसीपी/एआरएससी संजय कुमार नागपाल के कड़े पर्यवेक्षण में एक टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। टीम ने पहले दिल्ली के जीटी करनाल बाईपास और आईएसबीटी कश्मीरी गेट पर जाल बिछाया, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने लगातार निगरानी रखी और नाटकीय मोड़ में

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच से ट्रेन के रवाना होने से कुछ ही पल पहले ओम चंद उर्फ ओमु और उसके साथी प्यारे सिंह को पकड़ लिया।

अभियान के दौरान उनके पास से कुल 1.436 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जांच में यह पता चला कि चरस हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव के नोलू राम से ली गई थी। पुलिस ने नोलू राम के घर पर छापा मारा। लेकिन, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह फरार हो गया।

आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि मुंबई में चरस की काफी मांग है, खासकर पार्टी और इवेंट्स के लिए। उन्होंने बताया कि उन्हें यह नशीला पदार्थ मुंबई के ग्राहकों तक पहुंचाने का काम सौंपा गया था। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी हिस्सों का पता लगाने और अन्य शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

ओम चंद उर्फ ओमु शादीशुदा है और उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट टैक्सी चलाता है। प्यारे सिंह भी 12वीं कक्षा तक पढ़ा है और ओमु का चचेरा भाई है। दोनों एक ही गांव से संबंधित हैं।

इस कार्रवाई से दिल्ली में नशीले पदार्थों की अंतर-राज्यीय तस्करी पर बड़ा झटका लगा है और पुलिस ने दिखा दिया कि त्वरित कार्रवाई, सतर्कता और रणनीतिक योजना से अपराधियों को दबोचा जा सकता है। बरामद चरस और गिरफ्तार आरोपियों के साथ पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर रही है, ताकि इसके अन्य सदस्य भी जल्द पकड़े जा सकें।

क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20/29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं और समाज के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

10 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने उच्च गुणवत्ता वाली 1.031 किलो कोकीन जब्त की और इस ड्रग सप्लाई सिंडिकेट का मुख्य सदस्य को धर दबोचा। जब्त की गई कोकीन की बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी एक नाइजीरियन नागरिक है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिल्ली में कोकीन की सप्लाई

करता था और उसका नेटवर्क काफी बड़ा था। आरोपी का नाम जॉन चिबुइके (35 साल) है। वह मेहरौली के इस्लाम कॉलोनी में रहता है। जॉन पहले भी 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में शामिल था। ऑपरेशन कवच 13.0 के दौरान स्पेशल स्टाफ ने आरोपी जॉन चिबुइके को इस्लाम कॉलोनी स्थित उसके घर में घेरकर पकड़ा। टीम ने मैनुअल और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी को ट्रैक किया और उसके घर में रेड कर 1.031 किलो कोकीन जब्त कर ली। ऑपरेशन की टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर अनुज कुमार (आईसी/स्पेशल स्टाफ) ने किया और एसीपी अभिनेन्द्र जैन की देखरेख में यह कार्रवाई हुई। टीम में एसआई अमित ग्रेवाल, एसआई मनीष फोगाट, एचसी अक्षय, एचसी राकेश, एचसी संतवीर, एचसी मनीष, कॉन्सटेबल अंकित और कॉन्सटेबल सुरेन्द्र शामिल थे। यह कार्रवाई ड्रग सप्लाई चेन को काफी बड़ा झटका देने वाली है। आरोपी को पकड़ने के साथ ही मेहरौली थाने में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच अभी भी जारी है और स्पेशल स्टाफ पूरे सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सप्लाई चैन के अन्य सदस्य, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक भी ट्रेस किए जा रहे हैं। ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत दक्षिण जिला पुलिस लगातार नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस तरह की बड़ी सफलता से नशा तस्करी पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है।

कपिल मिश्रा ने इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को 'इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल' भारत हैबिटेट सेंटर में शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार द्वारा 3 से 5 अप्रैल तक चलाने वाले इस तीन दिवसीय फेस्टिवल में 100 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ता, 50 से अधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, साहित्यिक सत्र, युवा टाउनहॉल और विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत और समकालीन सांस्कृतिक विमर्श को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

कपिल मिश्रा ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इंद्रप्रस्थ नाम का चयन अपने आप में एक सांस्कृतिक घोषणा है। यह दिल्ली की उस ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास है, जिसे लंबे समय तक सीमित दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया जाता रहा। उन्होंने संगम टॉक्स और आयोजन से जुड़े सभी सहभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मंच, जहां संवाद तथ्य, तर्क और प्रमाण पर आधारित हो, वही समाज को सही दिशा देते हैं। जब विमर्श वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ता है, तब भ्रम और असत्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं। दिल्ली की बहुसांस्कृतिक पहचान पर प्रकाश डालते हुए मिश्रा ने कहा कि "दिल्ली 'मिनी इंडिया' के रूप में देश के हर क्षेत्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का केंद्र है। यहां देश के विभिन्न हिस्सों के

त्योहार और परंपराएं अपने सबसे व्यापक और जीवंत स्वरूप में दिखाई देती हैं। यही दिल्ली की वास्तविक पहचान है और उसी पहचान को सशक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों और पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि "राजधानी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नई ऊर्जा और व्यापकता दी गई है। कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव, यमुना तट पर छठ पर्व के भव्य आयोजन, तीज एवं नवरात्रि जैसे उत्सवों का व्यापक स्तर पर आयोजन और विश्वविद्यालयों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रमों का संचालन इन सभी प्रयासों ने दिल्ली की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी है।

कपिल मिश्रा ने कहा कि इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो रही है, जहां देशभर से जाने-माने इतिहासकार, लेखक, कलाकार और साहित्यकार एक मंच पर एकत्रित हुए हैं।

दिल्ली में रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, नगर निगम और पुरातत्व विभाग के चार कर्मचारी गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।

पहला मामला दिल्ली के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नगर निगम के एक बेलदार और एक जूनियर इंजीनियर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके मरम्मत किए गए मकान को न गिराने के बदले बेलदार ने उससे 80 हजार रुपए की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31 मार्च 2026 को मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

जांच के दौरान 1 अप्रैल 2026 को एजेंसी ने जाल बिछाया। इस दौरान बेलदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जब वह शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए अपने लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए 70 हजार रुपए मांग रहा था। मामला सामने आने के बाद जूनियर इंजीनियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरा मामला नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर क्षेत्र का है, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक संरक्षण सहायक समेत दो लोगों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे जारी किए गए एक नोटिस को रद्द करने और काम जारी रखने की अनुमति देने के बदले इन दोनों ने उससे 3 लाख 50 हजार रुपए की मांग की थी। बाद में बातचीत के बाद यह रकम 3 लाख 10 हजार रुपए पर तय हुई और शिकायतकर्ता से कहा गया कि वह एक लाख रुपए अग्रिम के रूप में दे।

इस शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 30 मार्च को मामला दर्ज किया। इसके बाद 1 अप्रैल को जाल बिछाकर एक आरोपी कर्मचारी को रंगेहाथों पकड़ लिया गया, जब वह एक लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। जांच के दौरान संरक्षण सहायक की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की आगे जांच जारी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगता है, तो वे इसकी शिकायत जरूर करें, ताकि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति मजबूत बनी हुई है: सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि राष्ट्रीय राजधानी में द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी हुई है, लेकिन 'बैकलॉग' की वजह से उपभोक्ताओं तक सिलेंडर आपूर्ति में वक्त लग रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ एक नियंत्रण कक्ष शुरू किया है, जहां इसकी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी के

खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का जोर पूरी दिल्ली में पीएनजी के दायरे को बढ़ाने पर है। वहीं दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त मिलिंद डुंबरे ने कहा कि पुलिस ने सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ राजधानी में अब तक 27 मामले दर्ज किये हैं।

राघव की चुप्पी पर कांग्रेस का सवाल, उदित राज बोले- सच्चाई सामने लाएं

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासी विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस नेता उदित राज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और राघव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

उदित राज ने कहा कि राजनीति में खामोशी की कोई जगह नहीं होती और राघव चड्ढा को इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी ने उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है तो यह भी स्पष्ट करना चाहिए, और यदि वे नाराज हैं तो वह भी सामने आना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने दो टूक कहा कि "खामोशी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो इस तरह के मुद्दों पर चुप रहना उचित नहीं है।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर

राघव चड्ढा को चुप किसने कराया है और इसके पीछे क्या कारण हैं।

उदित राज ने आगे कहा कि राजनीतिक मुद्दे कभी निजी नहीं होते, बल्कि पूरी तरह सार्वजनिक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अस्पष्टता या रहस्य पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने राघव से आग्रह किया कि वे सभी अटकलों पर विराम लगाने के लिए स्पष्ट बयान दें।

वहीं, राघव चड्ढा ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह संसद में लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। राघव ने अपने वक्तव्य में महंगाई, मध्यम वर्ग पर करों का बोझ, खाद्य पदार्थों में मिलावट और डिलीवरी कर्मियों की समस्याओं जैसे मुद्दों का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने संसद में उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है।

इस पूरे विवाद ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। एक ओर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पार्टी की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले समय में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

सिविल लाइंस में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, एक महीने में 10 हजार से ज्यादा चालान

नई दिल्ली। राजधानी के सिविल लाइंस ट्रैफिक सर्किल में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के चलते न केवल हजारों चालान किए गए हैं, बल्कि सड़क हादसों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

ट्रैफिक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मार्च महीने से शुरू हुए इस अभियान के तहत सबसे पहले कमला नगर मार्केट इलाके में 10 दिनों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 5200 चालान किए गए और 18 वाहनों को जब्त किया गया। इसके बाद राजपुर रोड पर भी 10 दिन का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 5500 से अधिक चालान किए गए। इन चालानों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना और अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन प्रमुख रूप से शामिल रहा।

इसी क्रम में बुलेवर्ड रोड पर गेट नंबर 3 और 4 के पास ऑटो चालकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष कार्रवाई की।

ब्रह्मपुरी में श्री हनुमान जन्मोत्सव पर 36वीं भव्य शोभायात्रा निकली

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। इस मौके पर 36वीं विशाल शोभायात्रा बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभायात्रा का आयोजन पंडित संजय गौड़ द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन को पूरे श्रद्धा भाव और

भव्यता के साथ संपन्न किया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब गया। इस दौरान महामंडलेश्वरों और कई संत-महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मानव शर्मा और अभिनेता साहस पुरसवानी सहित कई गणमान्य लोगों ने भी शोभायात्रा में हिस्सा लिया। शोभायात्रा की विशेष आकर्षण 50 से अधिक भव्य और आकर्षक झांकियां रहीं, जिनमें भगवान हनुमान के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों और धार्मिक कथाओं को जीवंत रूप में दर्शाया गया। मार्ग में जगह-जगह भंडारों और स्वागत मंचों की व्यवस्था की गई, जहां श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूरे क्षेत्र में "जय श्री राम" और "बजरंगबली" के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

केजरीवाल पर बरसी भाजपा, राघव विवाद ने बढ़ाया सियासी तापमान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल योग्य नेताओं से डरते हैं और पार्टी के भीतर असहमति को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

सचदेवा ने स्पष्ट कहा कि किसी भी दल को अपने नेताओं की नियुक्ति या पद से हटाने का अधिकार है, लेकिन किसी सांसद को संसद में बोलने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि राज्यसभा सचिवालय को इस प्रकार का निर्देश देना न केवल अनुचित बल्कि अलोकतांत्रिक भी है। उन्होंने कहा कि सांसद का कर्तव्य है कि वह जनता के मुद्दों को सदन में उठाए, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने केजरीवाल को "कमजोर और

भयभीत नेता" बताते हुए कहा कि वह पार्टी में मजबूत और स्वतंत्र विचार रखने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी या उन्हें किनारे किया गया।

इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह संसद में हमेशा आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है।

चड्ढा ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने महंगाई, मध्यम वर्ग पर करों का बोझ, खाद्य पदार्थों में मिलावट, डिलीवरी कर्मियों की समस्याएं और दूरसंचार कंपनियों की नीतियों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है।

इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा जहां इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना जताई जा रही है।

द्वारका में एक्सपायर खाद्य सामग्री बेचने का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में अपराध शाखा ने एक बड़े संगठित रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट एक्सपायर्ड और छेड़छाड़ किए गए खाने-पीने के सामान को दोबारा पैक करके बाजार में बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में नामी कंपनियों के उत्पाद भी बरामद किए हैं, जिन पर नकली निर्माण और समाप्ति तिथि छापी गई थी।

पुलिस के अनुसार 29 मार्च को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका के बामनोली गांव में एक गोदाम के अंदर अवैध तरीके से खाद्य पदार्थों की रीपैकेजिंग का काम चल रहा है। सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने पूरी योजना के साथ मौके पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य खाने-पीने के सामान पाए गए। जांच में सामने आया कि ये सामान या तो एक्सपायर हो चुके थे या उनकी

एक्सपायरी तारीख बहुत करीब थी। मौके पर मौजूद दो लोगों को पकड़ लिया गया, जिनकी पहचान शिवम सिंह और लोकेश कुमार के रूप में हुई।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे यह काम कमल मुदगिल के कहने पर कर रहे थे, जो इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक है। कुछ ही देर बाद कमल मुदगिल भी मौके पर पहुंच गया, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में आरोपी पहले बाजार से एक्सपायर या जल्द एक्सपायर होने वाले उत्पाद सस्ते दामों पर खरीदते थे। इसके बाद वे उन उत्पादों पर लिखी असली निर्माण और समाप्ति तिथि को केमिकल की मदद से मिटा देते थे। फिर विशेष मशीन के जरिए उन पर नई और नकली तारीखें छाप दी जाती थीं। इसके बाद सामान को नए कार्टन में पैक करके बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। इस प्रक्रिया के जरिए आरोपी न केवल लोगों को धोखा दे रहे थे, बल्कि उनकी सेहत के साथ भी गंभीर खिलवाड़ कर रहे थे।

छापे के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट जैसे खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। इसके अलावा, नकली तारीखें छापने वाली प्रिंटिंग मशीन और केमिकल भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल इस अवैध काम में किया जा रहा था। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया, जिसने उत्पादों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से बड़ी मात्रा में असुरक्षित खाद्य पदार्थों को बाजार में पहुंचने से रोका गया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे ऐसे अवैध कारोबार करने वालों में डर का माहौल बनेगा।

संपादकीय

चुनाव से पहले बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग-अलग मुद्दों पर वोटों का ध्रुवीकरण साफ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी मुख्य मुद्दा बन गया है। भाजपा जहां तुष्टीकरण और घुसपैठ के मुद्दे पर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अल्प संख्यक और बंगाली अस्मिता का कार्ड खेल रही है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण इसके अलावा नागरिकता पुनर्क्षिक्ण जैसे मुद्दे भी ध्रुवीकरण को हवा दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस व भाजपा के अलावा वामदल, कांग्रेस और हुमायूं कबीर भी चुनाव में अपनी उपस्थित दर्ज कराने में जुटे हैं। आखिरी मुकाबला दोध्रुवीय होने की संभावना है। कहा जा सकता है कि विधानसभा का मौजूदा चुनाव राज्य की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। कहा जा सकता है कि जबरदस्त टक्कर देने के बावजूद भाजपा यदि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता नहीं हिला पाई तो इसका प्रमुख कारण मुस्लिम वोट भी हो सकते हैं। जिसके साथ यह सवाल भी अहम हो गया है कि इस बार मुस्लिम मतों की प्रवृत्ति किस ओर रहेगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव का प्रमुख विश्लेषण हमेशा मुस्लिम मतों पर केंद्रित रहता है। कई वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की निरंतर जीत में मुस्लिम मतों की भूमिका प्रमुख मानी जाती रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी करीब 10.5 करोड़ है। जिसमें मुस्लिम मतदाता लगभग तीन करोड़ हैं। सवाल यह है कि मुस्लिम वोट इस बार किस ओर जाएंगे? बीते नतीजे बताते हैं कि मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, मालदा और साउथ 24 परगना जैसे जिलों में 85 ऐसी सीटें हैं, जिन पर मुस्लिम जनसंख्या 35 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें से 75 सीटें तृणमूल के पास हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों में 47 मुस्लिम चेहरे हैं। यानी करीब 18 प्रतिशत। पिछली बार की तरह ममता ने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं। ममता ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा टिकट कभी नहीं दिए। इसे हुमायूं कबीर, ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेता मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सहित कई दलों के नेता हुमायूं कबीर की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका भी कुछ असर हो सकता है। कहना कठिन है कि यदि हुमायूं कबीर का गठबंधन सौ से ऊपर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करता है तो उसका कुछ तो असर होगा ही।

सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) को समझना आवश्यक है। यही वह कानून है जो सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी राज्य में सीबीआई को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यही प्रावधान भारतीय संघवाद की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया गया है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह सहमति पूर्ण और अपरिहार्य नहीं है। कानून में ऐसे कई अपवाद मौजूद हैं, जहां सीबीआई बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय सीबीआई जांच का आदेश देता है, तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में, या केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

सीबीआई की सीमाएं और सवाल

-डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का राज्य क्षेत्राधिकार एक ऐसा संवेदनशील और बहुपरतीय मुद्दा बन चुका है, जो केवल कानूनी बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह विभिन्न राज्यों—विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों—ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति (जनरल कंसेंट) वापस ली है, उसने इस बहस को और अधिक तीखा बना दिया है। यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है कि क्या सीबीआई वास्तव में एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है या फिर वह केंद्र सरकार के प्रभाव में काम करने वाली संस्था बनती जा रही है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह दावा है कि राज्य सरकारें अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार जांच एजेंसियों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सच इन दोनों अतियों के बीच कहीं स्थित है।

सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को समझने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) को समझना आवश्यक है। यही वह कानून है जो सीबीआई को वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी राज्य में सीबीआई को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यही प्रावधान भारतीय संघवाद की उस भावना को दर्शाता है, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान किया गया है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह सहमति पूर्ण और अपरिहार्य नहीं है। कानून में ऐसे कई अपवाद मौजूद हैं, जहां सीबीआई बिना राज्य की सहमति के भी जांच कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय सीबीआई जांच का आदेश देता है, तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में, या केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की शक्ति सीमित है और उसे राष्ट्रीय हित तथा न्यायिक प्रक्रिया के सामने झुकना पड़ सकता है।

भारतीय संविधान का संघीय ढांचा भी इस पूरे विवाद को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को एक ₹सहकारी संघवाद₹ का उदाहरण माना जाता है, लेकिन यह पूर्णतः विकेंद्रीकृत नहीं है। सातवीं अनुसूची में कानून-व्यवस्था को राज्य सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में यह राज्यों का विषय है। लेकिन अनुच्छेद 246 और 254 के तहत केंद्र को विशेष परिस्थितियों में प्रधानता प्राप्त है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि राष्ट्रीय एकता और कानून का शासन किसी भी स्थिति में कमजोर न पड़े। यहीं से यह टकराव उत्पन्न होता है। एक ओर राज्य अपनी संवैधानिक स्वायत्तता का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र यह तर्क देता है कि राष्ट्रीय हित और व्यापक न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उसके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। सामान्य सहमति का अर्थ होता है कि सीबीआई राज्य में बिना हर बार अनुमति लिए जांच शुरू कर सकती है। इसकी वापसी के बाद सीबीआई को हर मामले में अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे जांच प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करती है। कई मामलों में यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अचानक जांच शुरू हो जाती है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं के मामलों में ढिलाई बरती जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2019 में सामान्य सहमति वापस लेते समय इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। इसी तरह अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी स्वायत्तता की रक्षा का कदम बताया।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार का यह कहना है कि राज्य सरकारें सहमति रोककर भ्रष्टाचार और अपराध की जांच में बाधा डाल रही हैं। यदि हर मामले में राजनीतिक अनुमति की आवश्यकता होगी, तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2021 में इस प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से अंतरराज्यीय और जटिल अपराधों की जांच प्रभावित होती है। यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक न्यायिक हितों के संदर्भ में देख रही है।

इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इससे जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जब किसी जांच एजेंसी पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सीबीआई को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं देखा जाएगा, तो उसके द्वारा की गई जांच और कार्रवाई भी संदेह के घेरे में आ जाएगी।

इसके साथ ही, राज्यों द्वारा सहमति वापस लेने की प्रवृत्ति भी एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि हर राज्य अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों को प्रवेश से रोकने लगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपराध नियंत्रण और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे अपराध जो कई राज्यों में फैले होते हैं, उनकी जांच के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता होती है।

समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और सहयोग में निहित है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि सीबीआई की स्वायत्तता को वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है और एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जिसमें न्यायपालिका और विपक्ष की भी भागीदारी हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीबीआई किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करे। दूसरे, डीएसपीई अधिनियम में संशोधन कर एक स्पष्ट और संतुलित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य सरकारें सहमति देने या न देने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर निर्णय लें। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो उसे स्वीकृति माना जाए। इससे जांच प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है। तीसरे, अंतरराज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से किया जा सके। सहकारी संघवाद का वास्तविक अर्थ यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर समस्याओं का समाधान करें, न कि एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हों। अंततः, यह समझना आवश्यक है कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता की परीक्षा भी है।

धर्म, अंधविश्वास और अपराध: जिम्मेदारी तय करने का समय

-डॉ. सत्यवान सौरभ

भारतीय समाज में धर्म और आस्था की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। सदियों से लोग अपने जीवन के सुख-दुख, समस्याओं और अनिश्चितताओं के समाधान के लिए धार्मिक व्यक्तियों, गुरुओं और ज्योतिषियों की शरण में जाते रहे हैं। आस्था अपने आप में एक निजी और सम्मानजनक विषय है लेकिन जब इसी आस्था का दुरुपयोग करके अपराधों को अंजाम दिया जाता है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का संकट बन जाता है।

हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ स्वयंभू बाबा, साधु या ज्योतिषी अपने कृत्यों को "धार्मिक प्रक्रिया" या "आध्यात्मिक उपचार" का नाम देकर महिलाओं के साथ शोषण, ठगी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देते पाए गए हैं। इन घटनाओं ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया है।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार का यौन शोषण या बलात्कार, चाहे किसी भी नाम या बहाने से किया जाए, जघन्य अपराध है। "धार्मिक विधि", "उपचार" या "आध्यात्मिक क्रिया" जैसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसे कृत्यों को सही ठहराना न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानून की दृष्टि में पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह एक सुनियोजित तरीका होता है, जिसके माध्यम से अपराधी अपने प्रभाव, पद और लोगों की आस्था का लाभ उठाकर उन्हें भ्रमित करता है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है-क्या केवल अपराधी ही दोषी है या पीड़ित और उसका परिवार भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं? यह सवाल समाज में अक्सर उठाया जाता है और कई बार लोग पीड़ितों पर ही उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन यह दृष्टिकोण न केवल संवेदनहीन है बल्कि समस्या के मूल कारणों को समझने में भी बाधा बनता है।

कई मामलों में देखा गया है कि ऐसे तथाकथित धार्मिक व्यक्ति पहले लोगों का विश्वास जीतते हैं। वे खुद को चमत्कारी शक्तियों से युक्त बताते हैं, समस्याओं का त्वरित समाधान देने का दावा करते हैं और धीरे-धीरे अपने अनुयायियों पर मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे पीड़ितों को इस हद तक प्रभावित कर देते हैं कि वे सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई महिला विरोध नहीं करती तो इसे सहमति मान लेना गंभीर भूल होगी।

इसके अलावा, सामाजिक दबाव, शर्म और बदनामी का डर भी एक बड़ा कारण होता है, जिसके चलते पीड़ित खुलकर सामने नहीं आ पाते। हमारे समाज में आज भी यौन अपराधों को लेकर पीड़ित को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति मौजूद है। ऐसे में कई महिलाएँ चुप रहना बेहतर समझती हैं। यह चुप्पी अपराधियों के लिए एक ढाल बन जाती है और वे अपने कृत्यों को बार-बार दोहराते रहते हैं। परिवार की भूमिका को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अगर परिवार अपने सदस्यों के प्रति अधिक सतर्क और जागरूक हो तो कुछ हद तक ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति, विशेषकर वयस्क, अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार रखता है। कई बार ये मुलाकातें परिवार की जानकारी के बिना होती हैं और कई बार परिवार भी उसी अंधविश्वास का हिस्सा बन चुका होता है। इसलिए केवल परिवार को दोषी ठहराना भी एक सरलीकृत और अधूरा दृष्टिकोण होगा।

अब सवाल उठता है कि क्या देश में मौजूद सभी बाबा और ज्योतिषी ऐसे ही हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से "नहीं" है। हर पेशे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ लोगों के कृत्य पूरे वर्ग की विश्वसनीयता को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इन तथाकथित धार्मिक और ज्योतिषीय गतिविधियों से समाज को वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यवस्था में बार-बार ठगी, शोषण और अपराध के मामले सामने आते हैं तो यह संकेत है कि उस व्यवस्था में कहीं न कहीं गहरी खामी है। ऐसे में सरकार और संबंधित संस्थाओं को चाहिए कि वे इस क्षेत्र का अध्ययन करें, आंकड़े एकत्र करें और यह मूल्यांकन करें कि समाज को इससे कितना लाभ और कितना नुकसान हो रहा है।

साथ ही, कानून का सख्ती से पालन भी अत्यंत आवश्यक है। जो लोग धर्म या आस्था का सहारा लेकर अपराध करते हैं, उनके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए होनी चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है- चाहे वह कितना ही प्रभावशाली या पूजनीय क्यों न माना जाता हो। लेकिन केवल कानून ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज और आम जनता की है। जब तक लोग बिना सवाल किए, बिना तर्क के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करते रहेंगे, तब तक ऐसे लोग पनपते रहेंगे। शिक्षा और जागरूकता इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान हैं। लोगों को यह समझना होगा कि आस्था और अंधविश्वास में अंतर होता है। आस्था व्यक्तिगत होती है, जबकि अंधविश्वास वह होता है जिसमें व्यक्ति तर्क और विवेक को छोड़ देता है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच और प्रश्न पूछने की आदत सिखानी होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी "धार्मिक प्रक्रिया" के नाम पर आपसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो असामान्य, असहज या निजी सीमा का उल्लंघन करता हो तो उस पर तुरंत सवाल उठाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कानून की मदद लेनी चाहिए।

मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। मीडिया को चाहिए कि वह ऐसे मामलों को जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करे, न कि सनसनीखेज तरीके से। साथ ही, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सकारात्मक और शिक्षाप्रद सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंततः, यह सामूहिक जिम्मेदारी है। अपराधी को सजा दिलाना जरूरी है लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है ऐसे माहौल का निर्माण करना, जहाँ अपराध पनप ही न सके। इसके लिए कानून, समाज, परिवार और व्यक्ति- सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी। धर्म का मूल उद्देश्य मानवता, नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देना है। यदि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर इन मूल्यों का उल्लंघन करता है तो वह न केवल कानून का अपराधी है बल्कि धर्म का भी अपमान करता है। ऐसे लोगों को पहचानना, उनके खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें कानून के दायरे में लाना हम सभी की जिम्मेदारी है। समय आ गया है कि हम आस्था और अंधविश्वास के बीच स्पष्ट रेखा खींचें।

कालीस्थान मंदिर, यहां पिंडी रूप में विराजमान हैं मां काली, जानिए कहां है यह मंदिर

हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहां देवी-देवताओं में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और श्रद्धा है। ऐसा ही मां काली का सिद्धपीठ है कालीस्थान मंदिर, जो नाहन में स्थित है। मां काली यहां पिंडी रूप में विराजमान है। रियासत कालीन शहर नाहन में ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर का निर्माण रियासत के राजा विजय प्रकाश ने अपनी रानी के आग्रह पर सन् 1730 ई. में करवाया था। यह रानी कुमाऊं के राजा कल्याण चंद की सुपुत्री थी, जोकि देवी की परम भक्त व उपासक थी। ऐसा माना जाता है कि राजा की सुपुत्री के साथ मां काली का साक्षात वास था। सिरमौर के राजा विजय प्रकाश के साथ रानी के विवाह के बाद मां काली साक्षात रूप में नाहन रियासत आई थीं। रानी के आग्रह पर ही आज कालीस्थान मंदिर में मां काली पिंडी रूप में साक्षात विराजमान हैं, जो भक्तों की रक्षा के साथ उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। पिंडी रूप में विराजमान होने के बाद राजा ने यहां मां के मंदिर का निर्माण करवाया। दशहरे और नवरात्र के अवसर पर यहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते थे। श्रद्धालु और सिरमौर का राजा एक साथ मिलकर पूजा में सम्मिलित होते थे। पहले नवरात्र में राजा लकड़ी के बक्से में जौ बीजने के बाद एक खांडे यानी दोधारी तलवार को रख देते हैं तथा नवमी को रियासत के राजगुरु जोकि नाथ संप्रदाय के होते हैं इस खांडे अथवा दोधारी तलवार को प्राप्त कर म्यान में रखते है। कालीस्थान मंदिर परिसर में भगवान शिव, शनि मंदिर, भैरव मंदिर, हनुमानजी के साथ-साथ विश्वकर्मा बाबा का मंदिर भी स्थापित है। वहीं परिसर में राधाकृष्ण मंदिर, मां बाला सुंदरी मंदिर तथा जाहरगोगा महाराज का मंदिर भी विराजमान है। मंदिर में पूजा-अर्चना का संचालन राजगुरु की उपाधि प्राप्त नाथ संप्रदाय के संतों द्वारा किया जाता है। नवरात्रों के अवसर पर यहां विशाल भंडारों का आयोजन होता है। वहीं लगभग 11 समाधियां राजगुरुओं की रिसायत कालीन दौर से स्थपित हैं। इस शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की मुरादें शीश झुकाते ही क्षण भर में पूरी होती हैं। दूर-दूर से श्रद्धालु मंदिर में नतमस्तक होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

आज का इतिहास

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

- 1768: फिलिप एस्ले ने माडर्न सर्कस का पहला शो पेश किया।
- 1769: हैदर अली ने पहले ऐंग्लो-मैसूर युद्ध में शांति की शर्तें तय कीं।
- 1818: अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिका के झंडे को मंजूरी दी।
- 1858: रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से भीषण युद्ध के बाद झांसी को छोड़ना पड़ा।
- 1905: कांगड़ा घाटी में आए भूकंप में 20,000 लोगों की मौत।
- 1949: उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन की स्थापना।
- 1979: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी।
- 1994: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बती बालक उग्येन थिनली दोरजी को नया करमापा घोषित किया।
- 1997: क्रयशक्ति की क्षमता की दृष्टि से विश्व बैंक ने भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया।
- 2001: चीन का अमेरिका विमान व चालक दल लौटाने से इनकार।
- 2001: फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति एरुत्रादा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल।
- 2004: भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर माओवादियों ने 18 भारतीय तेल टैंकरों में आग लगाई।
- 2006: इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर नए आरोप लगे।
- 2008: पाकिस्तान की नई सरकार ने सेना के खुफिया प्रमुख के पद से मेजर जनरल नदीम को हटाया।
- 2010: ओडिशा में माओवादियों के हमले में 10 सुरक्षाकर्मियों की मौत।

जन्म

- 1889: हिन्दी जगत के कवि, लेखक, पत्रकार माखन लाल चतुर्वेदी।
- 1908: भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम ऐजाज रसूल।
- 1915: भारत के महान क्रांतिकारी असित भट्टाचार्य।
- 1949: भारतीय अभिनेत्री परवीन बॉबी।

निधन

- 1987: हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय (सच्चिदानंद हीरानन्द वात्स्यायन)।
- 1995: भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता।

देश के सर्वोच्च सदन में उठती समान शिक्षा की पुकार

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत का संविधान अपने मूल में एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हों और वह अपने सामर्थ्य के अनुरूप विकास कर सके। यह विचार कहना होगा कि एक संवैधानिक संकल्प है जिसे अनुच्छेद 14, 21क और अन्य प्रावधानों के माध्यम से स्थापित किया गया है, किंतु जब हम शिक्षा के क्षेत्र में इस समानता की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं तब एक जटिल और विरोधाभासी परिदृश्य सामने उभरकर आता है।

वस्तुतः राज्यसभा में दिनेश शर्मा द्वारा उठाया गया प्रश्न इस विरोधाभास को और अधिक स्पष्ट करता है जिसमें उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त संरचनात्मक असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका यह तर्क कि "संविधान की समानता की भावना के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव मौजूद है!" भले ही ये कहना किसी राजनेता का हो, किंतु यह वक्तव्य भारत की हकीकत है, जोकि आज एक गहन संवैधानिक विमर्श का विषय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। यह संशोधन इस बात का प्रतीक था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ समानता और विशेषाधिकार के बीच संतुलन का प्रश्न उत्पन्न होता है।

राज्यसभा में प्रस्तुत विचारों के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधानों से छूट प्राप्त है जबकि अन्य संस्थानों को इन नियमों का पूर्णतः पालन करना होता है। दिनेश शर्मा ने इस स्थिति को अनुच्छेद 14 के साथ असंगत बताया और यह तर्क दिया कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की संरचनात्मक असमानता उत्पन्न होती है। यहां समझ लें कि यह प्रश्न प्रशासनिक अथवा कानूनी नहीं है, यह उस मूलभूत विचार से जुड़ा है कि क्या राज्य सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है? इस संदर्भ में अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट प्रदान कर एक तरह से देश में शिक्षा के व्यावहारिक स्तर पर एक असमान ढाँचे को भी वैधता प्रदान कर दी गई है। देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था में यह असमानता कानूनी प्रावधानों तक सीमित नहीं है, यह संरचनात्मक और व्यावहारिक रूप में भी स्पष्ट दिखाई देती है। भारत में सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और धार्मिक शिक्षण संस्थान इन सभी की गुणवत्ता संसाधन और अवसरों में भारी अंतर है। एक ओर महानगरों के निजी विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं और वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा सकता है। इस असमानता का परिणाम यह है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्र एक ही प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं किंतु उनकी तैयारी और अवसर समान नहीं होते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में समानता सुनिश्चित किए बिना बाल अधिकारों की वास्तविक रक्षा संभव नहीं है। आयोग की 2018 की एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "समान शिक्षा प्रणाली ही सामाजिक न्याय की आधारशिला बन सकती है।" वस्तुतः यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा में असमानता सिर्फ शैक्षणिक समस्या तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है।

भारतीय चिंतन परंपरा में भी शिक्षा को समानता का माध्यम माना गया है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक "एजुकेशन पॉलिटिक्स एंड वॉर" में लिखा है, "शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानार्जन नहीं है, इससे समाज में नैतिक और सामाजिक संतुलन स्थापित करना है।" इसी प्रकार महात्मा गांधी ने "हरिजन" में यह विचार व्यक्त किया कि "समान शिक्षा के बिना सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है।" इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा को व्यक्तिगत विकास का साधन होने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी माना गया है।

समान शिक्षा की आवश्यकता को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से यह जाति वर्ग और धर्म आधारित विभाजनों को कम कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह सभी को समान अवसर प्रदान कर प्रतिस्पर्धा को निष्पक्ष बना सकती है। राजनीतिक दृष्टि से यह लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है क्योंकि शिक्षित और जागरूक नागरिक ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं। वैचारिक दृष्टि से यह समाज में एकरूपता और समरसता को बढ़ावा दे सकती है। यह भी सच है कि समान शिक्षा लागू करने में अनेक चुनौतियाँ भी हैं। क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या भाषाई और सांस्कृतिक विविधता राज्यों के अधिकार और निजी क्षेत्र की भूमिका ये सभी कारक इस प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। अतः समाधान का मार्ग संतुलन में निहित है जहाँ समानता और विविधता दोनों का सम्मान किया जाए।

वर्तमान समय में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने का प्रयास किया है। इस नीति में समानता, समावेशन और गुणवत्ता पर विशेष बल दिया गया है। नीति के अंतर्गत स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा बहुभाषी शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की बात की गई है, किंतु इन नीतिगत प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर असमानता अभी भी बनी हुई है जिसका मुख्य कारण क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और संस्थागत विविधता है। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले सभी शिक्षण संस्थानों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए जाएँ जिनका पालन अनिवार्य हो। दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर सभी संस्थानों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण हो सके। चौथा संसद और नीति निर्माताओं को इस विषय पर सर्वसम्मिति से निर्णय लेना चाहिए ताकि शिक्षा को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठाया जा सके। अतः यहां कहने का तात्पर्य यही है क हम सभी यह स्वीकारें कि समान शिक्षा एक नीतिगत लक्ष्य न होकर देश हित में एक नैतिक आवश्यकता है। जब तक भारत के प्रत्येक बच्चे को समान गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक संविधान में निहित समानता का स्वप्न अधूरा ही रहेगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी है कि "शिक्षा वह शस्त्र है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं।" कहना होगा क यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था, इसलिए समय की मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए गंभीर और समन्वित प्रयास किए जाएँ। राज्यसभा में उठी यह बहस एक अवसर है, एक ऐसे भारत के निर्माण का जहाँ शिक्षा वास्तव में समान हो और हर नागरिक को अपने सपनों को साकार करने का समान अवसर प्राप्त हो सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 संपादक - आदित्य वशिष्ठ कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

मोदी, हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया : अमित शाह

दुधनोई (असम)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने इस रोडमैप को लागू करने के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

गोलपाड़ा जिले के दुधनोई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनीं। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और यहां असम में मुख्यमंत्री हैं-दोनों के पास राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप है। अगर लोग भाजपा को लगातार तीसरी बार जनादेश देते हैं, तो इसे (रोडमैप) आगे बढ़ाया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी कल्याण की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों के विकास पर केवल 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में उनके लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये दिए।

गृह मंत्री ने ग्वालपाड़ा को 'मिनी असम' करार दिया, क्योंकि वहां राभा, बोडो, हाजोंग और कोच सहित कई जनजातियों के लोगों के अलावा आदिवासी चाय बागान श्रमिक रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही इन लोगों का विकास सुनिश्चित कर सकती है। शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को डराने के लिए अफवाहें फैला रही है कि वे यूसीसी से प्रभावित होंगे, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है और कोई भी आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने आदिवासियों की कला, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। मैं सहकारिता मंत्री के रूप में इसे सुनिश्चित करूंगा। असम से सटी मेघालय की गारो पहाड़ियों में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके गारो परिषद में सत्ता हथियाने की कोशिश की और इसी वजह से यह संघर्ष शुरू हुआ।

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर असम को घुसपैठियों का 'अड्डा' बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शाह ने कहा कि हमें असम में पांच साल और सरकार चलाने का मौका दीजिए। हम प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान कर उन्हें वापस भेजेंगे और राज्य को उनसे मुक्त कराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 से कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके असम में शांति बहाल की और 10,000 से अधिक युवाओं का आत्मसमर्पण कराने के बाद उन्हें मुख्यधारा में ले आई।

शाह ने आरोप लगाया कि वह जब भी असम आंदोलन के दिनों से राज्य में व्याप्त अशांति के बारे में बात करते हैं, तो 'राहुल बाबा (कांग्रेस नेता राहुल गांधी) कहते हैं कि मैं अतीत की बात क्यों करता हूं।' उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की ओर से अतीत में की गई गलतियों को याद रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें दोहराया न जाए।

शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतती है, तो पूर्वोत्तर राज्य को एक बार फिर अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री ने असम में भाजपा की ओर से शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इस पैमाने की पहल करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पंजे' (कांग्रेस का चुनाव चिह्न) पर एक भी वोट बर्बाद न करें। 'कमल' (भाजपा का चुनाव चिह्न) के पक्ष में वोट डालें। शाह ग्वालपाड़ा वेस्ट (सुरक्षित) से भाजपा उम्मीदवार पबित्रा राभा और दुधनोई (सुरक्षित) से पार्टी प्रत्याशी टंकेश्वर राभा के लिए प्रचार कर रहे थे। असम की 126 विधानसभा सीट के चुनाव के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा, जबकि मतों की गिनती चार मई को की जाएगी।

जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा राष्ट्र की अमूल्य पूंजी: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देश के युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्र की अमूल्य सामाजिक पूंजी बताते हुए उन्हें खेलों में सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है।

एक लेख के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक प्रतिभा को उचित प्रशिक्षण और संसाधनों के जरिए निखारकर देश खेल जगत में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति ने जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों की सहज खेल प्रतिभा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये बच्चे सीमित संसाधनों के बावजूद प्रकृति के बीच अपने खेल संसार का निर्माण कर लेते हैं। मिट्टी, पेड़ों, बीजों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके वे खेल के साधन तैयार करते हैं और पूरे उत्साह के साथ खेलते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक रुझान और ऊर्जा यदि आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाओं से जुड़ जाए, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने में सक्षम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए ओडिशा की 15 वर्षीय खिलाड़ी अंजलि मुंडा का उल्लेख किया, जिसने 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक जीते और देशभर के युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उसे पहचानने और सही दिशा देने की।

राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज में तीरंदाजी जैसी खेल विधाओं की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रही है। उन्होंने 'संताथ हूल' जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय भी जनजातीय वीरों के युद्ध कौशल, विशेषकर तीरंदाजी की प्रशंसा की गई थी। साथ ही उन्होंने एकलव्य को प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनकी महानता आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करती है। मुर्मु ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर किए जा रहे छोटे-छोटे प्रयास भी जनजातीय प्रतिभाओं को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके गांव में भी वंचित वर्गों के बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है, जहां खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, टीम भावना और आत्मविश्वास को भी विकसित करता है।

खेलों के माध्यम से युवाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेलों में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आपसी मित्रता और सहयोग की भावना भी विकसित होती है, जो समाज को मजबूत बनाती है। राष्ट्रपति ने 'खेलो इंडिया' अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल ने देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि पहले खेल सुविधाएं मुख्यतः महानगरों तक सीमित थीं, लेकिन अब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी खेल अकादमियों और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

उन्होंने 'खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026' जैसे आयोजनों को जनजातीय खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताते हुए कहा कि इससे जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को पहचान और अवसर मिल रहा है। इस तरह के प्रयासों से देश में खेलों का एक समावेशी इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, जिसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके। राष्ट्रपति ने भारतीय खेल इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने 1928 में हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें जनजातीय खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने वर्तमान समय के खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी जनजातीय समुदाय के खिलाड़ी भारतीय टीमों को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में आयोजित विभिन्न खेल आयोजनों, जैसे बस्तर और सरगुजा ओलंपिक में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली है। इनमें से कई युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने भटकाव के रास्ते को छोड़कर खेलों के माध्यम से सकारात्मक दिशा अपनाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय युवाओं सहित देश की युवा पीढ़ी की खेल प्रतिभा भारत की अमूल्य सामाजिक पूंजी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतिभा का सही उपयोग करते हुए भारत खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छुएगा और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करेगा। अपने संदेश के अंत में राष्ट्रपति ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया! खूब खेलो इंडिया!

कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र को एकतरफा बताया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने 16-18 अप्रैल तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को एकतरफा बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की तरफ से इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ पत्राचार भी किया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ दिखावा था और सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने का पहले ही मन बना चुकी थी।

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच हुए पत्राचार का ब्योरा देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। 16 मार्च को रिजिजू ने खरगे को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन के लिए कांग्रेस से चर्चा की इच्छा जताई। खरगे ने उसी दिन जवाब दिया कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और लिखित प्रस्ताव देना चाहिए। 24 मार्च को विपक्षी दलों ने रिजिजू को फिर से एक पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वर्तमान में कई राज्यों में चुनाव और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है इसलिए 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाई जाए। 26 मार्च को रिजिजू ने फिर से खरगे को पत्र लिखा और कहा कि हम दोबारा मांग करते हैं, कांग्रेस हमसे मिले और बातचीत करे, ताकि हम संविधान संशोधन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं।

खरगे ने जवाब दिया कि सभी दलों को बुलाकर एक बैठक कीजिए और 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए। 16 से 26 मार्च तक खतों का आदान-प्रदान हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही मन बना चुकी थी कि विशेष सत्र बुला लिया जाए। अंत में रिजिजू ने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव रमेश ने कहा कि रिजिजू ने अपने सारे खतों में सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की है लेकिन अब साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर नहीं है बल्कि परिसीमन को लेकर भी है।

असम को नहीं बनने देंगे लव जेहाद एवं लैंड जेहाद की धरती : योगी आदित्यनाथ

बरपेटा (असम)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार दीपक कुमार दास के पक्ष में बरपेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एवं एआईयूडीएफ पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई, जबकि एआईयूडीएफ को भी बंगाल की खाड़ी में फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने असमवासियों से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने का आह्वान किया और कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है और असम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देना है। राजग का संकल्प है कि असम को लव जेहाद-लैंड जेहाद की धरती नहीं बनने देंगे। यहां घुसपैठ नहीं होने देंगे। कांग्रेस व यूडीएफ की घुसपैठियों के जरिये डेमोग्राफी बदलने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। एक-एक घुसपैठी को चिह्नित कर यहां से बाहर करने की भी व्यवस्था हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने तय किया है कि असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनने देंगे और दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे। कांग्रेस एवं एआईयूडीएफ को जब भी अवसर मिला, इन्होंने भारत व भारतीयता को अपमानित किया। एआईयूडीएफ असम में घुसपैठ की जननी है। घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनकी सहयोगी बनकर असम की संस्कृति से खिलवाड़ कर रही है। वहीं राजग सरकार असम की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करते हुए हर घुसपैठिए को बाहर कर डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश को विफल कर रही है।

उन्होंने असमवासियों को रंगाली बिहू उत्सव की शुभकामना देते हुए असम को भारत के गौरव की धरा बताया और कहा कि हर भारतवासी यहां मां कामाख्या के दर्शन करने आता है। यहां की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व समृद्ध परंपरा ने 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन किया है। वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव व माधव देव की पावन धरा ने नई ऊंचाई के साथ इसे एकता, भक्ति व मानवता के संदेश की भूमि के रूप में परिवर्तित किया है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के साथ जैव विविधता के लिए जग विख्यात है। अहोम राजवंश ने इसी पावन धरा में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाकर अहोम की समृद्ध संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाकर भारत की रक्षा में योगदान दिया था। अहोम राजवंश के महान नायक लचित बोरफुकन का अदम्य साहस, शौर्य व पराक्रम भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा रहा है। असम ने मेहनत, परिश्रम व पुरुषार्थ से चाय की चुस्की को दुनिया तक पहुंचाया। असम अब चाय के साथ चिप के उत्पादन की केंद्रभूमि भी बन रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में भारत रत्न केवल एक खानदान के लोगों को प्राप्त होता था। असम के संगीत एवं संस्कृति की पहचान भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मोदी सरकार ने और गोपीनाथ बोरदोलोई को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिया। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्षों तक असम में अराजकता, दंगा, कर्फ्यू, घुसपैठ को बढ़ावा देकर सुरक्षा में सेंध लगाई और विरासत को अपमानित किया।

कांग्रेस को मां कामाख्या कॉरिडोर, काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडा संरक्षण, असम एवं पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी याद नहीं आई। आज पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क, रेल, एयरपोर्ट व इनलैंड वाटरवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है और यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से संवाद करते हुए कहा कि देश में जहां-जहां राजग सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वहां-वहां विकास और विरासत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामजन्मभूमि के लिए आंदोलन चला।

उज्जैन में विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

भोपाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन वह स्थान है जहां अध्यात्म और विज्ञान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और एक नई दृष्टि का जन्म होता है। भारत के जितने भी प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं, चाहे वह उज्जैन हो, काशी हो, कांची हो या पुरी धाम, सभी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ऐसी 'जीती-जागती प्रयोगशालाएं' हैं, जहां विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय मिलता है।

केंद्रीय मंत्री प्रधान शुक्रवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'महाकालः द मास्टर ऑफ टाइम' के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाकालः द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे विद्वानों और विशेषज्ञों का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के अटूट संबंध पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है और इसका सबसे सटीक उदाहरण स्वयं उज्जैन नगरी और महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में दिखाई देता है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने महाकाल मंदिर के एक वैज्ञानिक अनुष्ठान का उल्लेख करते हुए बताया कि वैशाख मास के पहले दिन से भगवान शिव के ऊपर मटके से निरंतर जल की धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ग्रीष्मकाल की चुनौतियों का एक वैज्ञानिक समाधान और पर्यावरणीय प्रबंधन है।

यह दर्शाता है कि हमारा समाज सदियों से काल गणना और प्रकृति के बदलावों के अनुसार अपनी जीवनशैली को ढालने की वैज्ञानिक समझ रखता था। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व और संतुलित जीवन प्रवाह हमेशा से केंद्र में रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उज्जैन वह स्थान है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यहीं से प्राचीन काल में दुनिया की काल गणना होती थी, इसलिए अब समय आ गया है कि हम 'ग्रीनविच मीन टाइम' (जीएमटी) के स्थान पर 'महाकाल स्टैंडर्ड टाइम' (एमएसटी) की तार्किक स्थापना करें। उन्होंने कहा कि आधुनिक एआई उपकरण भी यह स्वीकार करते हैं कि काल गणना का मूल केंद्र उज्जैन के आसपास का क्षेत्र है, अतः हमें अपने वैज्ञानिक स्वाभिमान को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करना होगा और यह इस विमर्श का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन धर्म की नगरी होने के साथ विज्ञान की भी नगरी है। उज्जैन की माटी में विज्ञान, गणित, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन सदियों से विद्यमान है। उज्जैन काल गणना का केंद्र रहा है, जहां प्राचीन काल में सूर्य की छाया से समय नापने की कला विकसित हुई। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है और इसे पृथ्वी का मध्य बिंदु माना जाता था।

ग्रीनविच के वैश्विक मानक के अस्तित्व में आने से सदियों पहले शून्य देशांतर रेखा पावन नगरी उज्जैन से होकर गुजरती थी। जब पश्चिम में खगोल शास्त्र का ज्ञान भी नहीं था तब उज्जैन के ज्योतिषी और विद्वान काल गणना कर नक्षत्रों की स्थिति बता रहे थे। प्रख्यात चिंतक एवं लेखक सुरेश सोनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में काल (समय) की अवधारणा अत्यंत गहन और वैज्ञानिक है। भारतीय कालगणना खगोलीय पिंडों की गति, ऋतु चक्र और प्रकृति के नियमों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य की समग्र प्रगति के लिए विज्ञान एवं तकनीक, कला, अध्यात्म, सामाजिकता और सामाजिक अर्थशास्त्र के बीच संतुलित समन्वय आवश्यक है। उज्जैन में स्थापित कालयंत्र इस प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है।

राघव चड्ढा ने आआपा हाईकमान पर दागे सवाल, कहा मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाए जाने से आहत सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सवाल दागे हैं। आआपा ने राज्यसभा सचिवालय से राघव के स्थान पर अशोक मित्तल को नियुक्त करने की सिफारिश की है। मित्तल जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। पंजाब में वर्ष 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राघव आआपा का प्रमुख चेहरा रहे हैं। पिछले कुछ समय से वह पंजाब की राजनीति से दूर हैं।

राघव चड्ढा ने आज सुबह एक वीडियो जारी किया। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। मुझे जब-जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं आम आदमी के मुद्दे उठाता हूं। संसद में ऐसे मुद्दों पर बोलता हूं जिन्हें आमतौर पर सदन में उठाया नहीं जाता। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता के मुद्दे उठाना, जनता के मुद्दों पर बात करना अपराध है। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? चड्ढा ने कहा कि यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह लिखकर दिया है कि राघव चड्ढा के सदन में बोलने पर रोक लगा दी जाए। बोलने का मौका न दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा। मैं जब बात करता हूं तो देश के आम आदमी की बात करता हूं।

संसद में एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, टोल व बैंक लूट का मुद्दा उठाया। मिडिल क्लास से हो रही लूट, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे उठाने के बाद आम आदमी का फायदा हुआ लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ।

मेरी आवाज को कोई क्यों बंद करना चाहेगा। आप लोग मुझे असीमित प्यार देते हैं। मेरा हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे ही मेरा हाथ और साथ थामे रखिएगा। छोड़िएगा मत। मैं आप से हूं, आपके लिए हूं। जिन लोगों ने संसद में बोलने का हक छीन लिया उनके लिए कहना चाहूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।

संक्षिप्त खबरें

राप्ती नदी में डूबे चार नाबालिगों के शव बरामद

गोरखपुर। गोरखपुर में कथित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के दौरान राप्ती नदी में डूबे चार नाबालिगों के शव तीन दिन चले तलाशी अभियान के बाद बरामद कर लिए गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यह घटना बुधवार को गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र के मिर्जापुर घाट के पास हुई, जहां नौ लड़कों का एक समूह साइकिल से गया था। पुलिस ने बताया कि इनमें से पांच लड़के नहाने और वीडियो बनाने के लिए पोंटून पुल के पास नदी में उतरे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने लगे। उसने बताया कि उनमें से एक राजकरण उर्फ 'टाइमपास' तैरकर बाहर निकल आया और उसने अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को मौके पर तैनात कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से साइकिल, कपड़े और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। उसने बताया कि पानी में डूबे लड़कों में से एक विवेक निषाद (15) का शव बृहस्पतिवार शाम को घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर मिला जबकि अमन उर्फ बीरू राजभर (15), गगन पासवान (15) और अनिकेत यादव (13) के शव शुक्रवार सुबह पानी की सतह पर आए गए जिन्हें गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सिलेंडर में रिसाव से घर में लगी आग, दम घुटने के कारण एक व्यक्ति की मौत

मेरठ। मेरठ में एक मकान में गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण लगी आग लगने के बाद दम घुटने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की लोधी वाली गली में बृहस्पतिवार देर रात हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव हो रहा था और माचिस जलाते ही आग भड़क उठी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक योगेश नामक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो चुकी थी और वह आंशिक रूप से झुलस भी गया था। नगर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए दमकल विभाग के साथ समन्वय कर जांच की जा रही है।

युवती की हत्या में फरार आरोपित गिरफ्तार

देवरिया। जनपद देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का पुलिस ने अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनंद कुमार पाण्डेय ने बताया कि मदनपुर के बरांव निवासी वीर बहादुर उर्फ शिवम को दो अप्रैल की रात को सेमरा पुल जाने वाले मार्ग के पास से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ इसी गांव के रहने वाले शिवानंद प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था आरोपित बेटी से शादी करने का दबाव डाल रहा था, जबकि वह इस रिश्ते के खिलाफ थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपित ने खुन्नस में आकर एक अप्रैल की रात को युवती की हत्या कर दी थी। आरोपित वारदात के बाद से फरार चल रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली गई है। एएसपी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

एक एसआई और तीन चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह ने जिले के तीन चौकी इंचार्ज और एक एसआई को विवेचना में लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी आरती सिंह ने बताया कि प्रभारी चौकी पल्ला विजय कुमार, प्रभारी चौकी ताजपुर अनिल सिकरवार एवं प्रभारी चौकी बबना इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव एवं शिकायत जांच प्रकोष्ठ के उप निरीक्षक अमर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को शिकायत जांच प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया। एसपी आरती सिंह ने बताया चौकी इंचार्जों द्वारा विवेचना में लापरवाही की गयी है। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सशक्त और विकसित राष्ट्र के लिए कृतसंकल्पित है भाजपा : कृषि मंत्री

देवरिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को आगामी कार्यक्रमों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है।

उन्होंने कहा कि भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी संतराज यादव ने कहा कि 05 अप्रैल से 12 अप्रैल तक पार्टी के कार्यक्रम चलाए जाने की

कार्ययोजना है उसके बाद 14 अप्रैल को बना साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 5, 6, 7 को बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक के कार्यालयों को सजाया जाएगा तथा 06 अप्रैल को पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यालयों पर झंडारोहण कराया जाएगा तथा सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर भी पार्टी का झंडा लगाएंगे। हर बूथों पर प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य, तथा गणमान्य व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। 08 अप्रैल को सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन देवरिया क्लब सभागार में 11 बजे कराया जाएगा। पूरे जनपद में लगभग 2700 सक्रिय सदस्य हैं। ग्राम बस्ती संपर्क अभियान 7 से 12 अप्रैल तक चलाया जाएगा जिसमें पार्षद से लेकर प्रदेश पदाधिकारी भाग लेंगे। इस दौरान मंडलों में गोष्ठियों का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें जनपद के विभिन्न पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का कार्यक्रम भी किए जाएंगे तथा गांवों में 25 से 30 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए इन सभी कार्यक्रमों को हमे मिलजुल कर संपादित करना है। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के जिला संयोजक अजय कुमार दुबे ने किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कुमार दुबे, मारकंडे शाही, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष छठे लाल निगम, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा, संजय सिंह एडवोकेट, गंगा सिंह कुशवाहा, महामंत्री श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, रविंद्र कौशल, नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा, अंकुर राय, सत्यप्रकाश पांडे, विजय पांडे, वीरेंद्र सिंह, राजन यादव, उमापति सिंह, प्रणव दुबे, सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

2027 में प्रचंड बहुमत से फिर बनेगी भाजपा सरकार : उपमुख्यमंत्री

प्रयागराज। वर्ष 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, जबकि अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यह बातें शुक्रवार को मीडिया से प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है। 2027 के चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी पार्टी के विधायक एक ही वाहन में जाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। उन्होंने पीडीए को लेकर भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए के साथ न पिछड़ा है और न ही दलित है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत मोदीमय और भाजपामय है तथा महिलाएं, बेटियां और नौजवान सभी भाजपा के साथ हैं। वहीं संभल के एसपी केके बिश्नोई की शादी में सपा विधायकों के शामिल होने पर अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत घटिया बात है। विवाह समारोह में यदि किसी को निमंत्रण मिलता है तो लोग दल और जाति से ऊपर उठकर शुभकामनाएं देने जाते हैं। उन्होंने एसपी संभल केके बिश्नोई और एसपी बरेली अंशिका वर्मा को शादी की शुभकामनाएं भी दीं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव इस समय सत्ता पाने के लिए बेचैन हैं और पत्रकारों की तरह सवाल उठा रहे हैं तथा ट्विटर पर खबरें पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के पास इस समय धरातल पर कुछ नहीं है, जबकि भाजपा के पास समर्पित और देश सेवा की भावना से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं।

पेपर लीक मामले में फरार कृष्णा पाण्डेय को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

वाराणसी। प्रयागराज के थाना सिविल लाइन में समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 के पेपर लीक मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी की धाराएं 420, 467, 468 और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में फरार कृष्णा पाण्डेय को यूपी एसटीएफ ने वाराणसी के अखरी बाईपास के पास से गिरफ्तार किया। यह जानकारी एसटीएफ ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।पेपर लीक मामले में जांच यूपी एसटीएफ को मिलने के बाद से इस मुकदमे में आरोपित सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय को वर्ष 2024 जून में गिरफ्तार कर लिया गया था और तभी से कृष्णा पाण्डेय की तलाश चल रही थी। मुखबिर की सूचना पर वाराणसी में छिपे हुए कृष्णा की गिरफ्तारी संभव हो सकी।

म्यूल अकाउंट जांच में साइबर क्राइम टीम की बड़ी कार्रवाई, 60 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन का खुलासा

देवरिया। साइबर क्राइम पुलिस टीम ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट के जरिए फर्जी लेन-देन करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनंद कुमार पाण्डेय ने आज बताया कि थाना साइबर क्राइम टीम ने 2 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए बरहज थाना क्षेत्र के बेलडाड़ मोड़ के पास से आरोपित माखन लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया।

वह बरगइया टोला, जयनगर वार्ड नंबर-4 का निवासी है। जांच में सामने आया कि उसने "लेक्सी रुफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड" नाम से एक डमी कंपनी बना रखी थी, जिसके जरिए कई बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। इस नेटवर्क में कुल 9 खाते शामिल पाए गए। इन खातों पर विभिन्न राज्यों से एनसीआरपी पोर्टल पर 46 शिकायतें दर्ज

हैं। पुलिस के अनुसार, इन खातों के माध्यम से अब तक करीब 60 करोड़ रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनंद कुमार पाण्डेय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित के पास से 11 चेकबुक, 9 एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, विभिन्न कम्पनियों के एग्रीमेंट दस्तावेज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी के एमओए और एओए सहित बड़ी संख्या में कागजात बरामद किए गए। इसके अलावा एक एप्पल मोबाइल फोन और दो डेल लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना साइबर क्राइम देवरिया में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 66D में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य फरार आरोपितों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लेन-देन की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में दें।

हाईकोर्ट ने उप्र सरकार के एसीएस होम से मांगा जवाब

केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे सम्मानसूचक शब्द क्यों नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के साथ सम्मानसूचक शब्द न लगाए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को हलफनामा दाखिल कर इस चूक का कारण बताने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि एफआईआर में एक स्थान पर केंद्रीय मंत्री का नाम बिना किसी सम्मानसूचक शब्द जैसे 'माननीय' या 'श्री' के सीधे लिखा गया।

इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि भले ही शिकायतकर्ता ने मंत्री का उल्लेख इस तरह किया हो लेकिन पुलिस का दायित्व था कि एफआईआर दर्ज करते समय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उचित सम्मानसूचक शब्द

जोड़े जाएं। अदालत ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आपराधिक धमकी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़े आरोपों को चुनौती दी गई और उसी एफआईआर में सम्बंधित केंद्रीय मंत्री का नाम भी शामिल है।

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश दिया कि वह यह निर्देश 48 घंटे के भीतर सम्बंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश हर्षित शर्मा व दो अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। मामला मथुरा का है।

तलाकशुदा पत्नी को मोटरसाइकिल से बांधकर घसीटा, पति गिरफ्तार

बहराइच। जिले में एक व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को मोटरसाइकिल से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए कथित तौर पर उसकी हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई, जिसमें महिला व आरोपी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, रामगांव क्षेत्र के मुसल्लमपुर गांव निवासी रहीस ने करीब एक वर्ष पहले नानपारा निवासी रेशमा से शादी की थी लेकिन आपसी विवाद के कारण दोनों का जनवरी में तलाक हो गया, जिसके बाद महिला अपने मायके में रह रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी बुधवार को नानपारा आया था और लक्ष्मणपुर मतेही गांव के पास घर लौट रही अपनी तलाकशुदा पत्नी से उसका आमना-सामना हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने बताया कि रहीस ने पहले महिला को मोटरसाइकिल से टक्कर मारी और फिर उसे वाहन से बांधकर सड़क पर घसीटा। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया।

स्थानीय लोगों ने गुस्से में आरोपी की पिटाई कर दी, जिससे वह भी घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। नानपारा के क्षेत्राधिकारी पहुप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें हत्या का प्रयास, चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी और अपमान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

किसान का शव नीम के पेड़ में फंदे से लटका मिला

प्रयागराज। जिले में स्थित सराय ममरेज थाना के पास शुक्रवार को घर से कुछ दूर स्थित नीम के पेड़ से किसान का शव फंदे से लटका पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि सरायममरेज थाना क्षेत्र में रहने वाला राजेंद्र कुमार (50) खेती करके दो बेटी एक बेटा का किसी तरह भरण पोषण करता था। शुक्रवार सुबह पता चला कि घर से कुछ दूर पर स्थित बगीचे में एक नीम के पेड़ से राजेंद्र का शव लटका हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बीएसएफ जवान की हत्या का खुलासा, पत्नी समेत 5 गिरफ्तार

मेरठ। जिले के इंचौली थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान नैन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। शुक्रवार को एसएसपी अविनाश पांडेय ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ग्राम धनपुर में 27-28 मार्च की रात करीब 1:40 बजे नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि बीएसएफ कांस्टेबल नैन सिंह (35) की हत्या के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में जान गंवाने वाले बीएसएफ कांस्टेबल की पत्नी भी शामिल है। पांडे ने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि जान गंवाने वाला बीएसएफ का कांस्टेबल अपनी

पत्नी कोमल को गुलशन (क्षेत्र के निवासी) के साथ संबंध होने के कारण अक्सर ताना मारता था और अपमानित करता था। उन्होंने कहा कि इसी रंजिश के कारण आरोपियों ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपियों ने नैन सिंह की सोते समय गोली मारकर हत्या करने की बात कबूल की।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुलशन, कोमल (जान गंवाने वाले जवान की पत्नी), राहुल उर्फ पवन, गुड्डु और मोंटू के रूप में हुई है। आरोपियों द्वारा दिए गए सुराग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अवैध देशी पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि 35 वर्षीय बीएसएफ जवान शनिवार (28 मार्च) शाम को मेरठ जिले में अपने घर पर मृत पाया गया और उसके शरीर पर गोली का घाव था। उन्होंने बताया कि घटना जिले के इंचौली थाना क्षेत्र स्थित धनपुर गांव की है। थाना प्रभारी बजरंग प्रसाद ने बताया कि बीएसएफ कांस्टेबल नैन सिंह (35) छुट्टी लेकर घर आए थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। परिवार के सदस्यों ने कहा कि सिंह पश्चिम बंगाल में तैनात थे और छह मार्च को घर आए थे।

इस संबंध में मृतक के पिता गरीबदास की लिखित शिकायत पर 28 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। शुरुआती शिकायत में पड़ोसियों का नाम लिया गया था। पुलिस ने कहा, "चश्मदीदों की अनुपस्थिति में पुलिस ने तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर जांच की।"

निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से दो मजदूरों की मौत, चार घायल

देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में शुक्रवार को पालिका परिसर के पास एक निर्माणाधीन भवन में पुरानी जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी, उप जिला मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड निवासी आशीष कनोडिया अपने भूखंड पर भवन निर्माण करा रहे थे। निर्माण कार्य एक ठेकेदार के जिम्मे था, जिसने राघव नगर से मजदूरों को बुलाकर बेसमेंट की खुदाई शुरू कराई थी। शुक्रवार सुबह 11 बजे निर्माण

स्थल पर करीब 24 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान उत्तर दिशा की एक पुरानी और कमजोर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों की मदद अन्य मजदूरों ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बरियापुर के सेमरहीं निवासी गोविंद और गौरीबाजार निवासी योगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम में रखवाया है।

वहीं, घायलों में शारदा राजभर (अहिल्यापुर), अखिलेश कुमार (भगवान छापर) और हरेन्द्र चौहान (टड़वा) समेत अन्य एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है।

योगी सरकार की पहल से बदली हमीरपुर की कीर्ति की जिंदगी

'प्रेरणा कैंटीन: सामूहिक प्रयास से बना 1.25 करोड़ के टर्नओवर का मॉडल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की योजनाएं आज ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहीं हैं। हमीरपुर जनपद की कीर्ति इसकी जीवंत मिसाल बनकर उभरीं हैं। एक समय अध्यापिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली कीर्ति ने जब महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, तो यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

वर्ष 2018 में समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी, बल्कि समाज में खुद की एक नई पहचान भी बनाई। आज वही कीर्ति "प्रेरणा कैंटीन" के माध्यम से न सिर्फ खुद सशक्त हुईं हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दे रहीं हैं। वर्ष 2025 अगस्त में कीर्ति ने 10 महिलाओं के साथ मिलकर हमीरपुर के दरियापुर स्थित

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में "प्रेरणा कैंटीन" की शुरुआत की। लगभग 11 लाख रुपये के निवेश से शुरू हुआ यह प्रयास आज उनके लिए सफल उद्यम बना, जिसका टर्नओवर 1.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वर्तमान में कैंटीन से 08 महिलाएं जुड़ीं हैं। हर महीने प्रत्येक महिला को लगभग 8,000 वेतन मिल जाता है। यह कैंटीन केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि पोषण और स्वच्छता का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां 332 बच्चों को रोजाना पौष्टिक नाश्ता, दूध और भोजन बेहद किफायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षकों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है।

कीर्ति का मानना है कि स्वच्छ और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ समाज की नींव है, और इसी सोच के साथ वह पूरी जिम्मेदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। कीर्ति सिंह की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं विशेषकर स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की उपयोगिता का प्रमाण है। कीर्ति ने पहले बैंक सखी के रूप में काम करते हुए अनुभव हासिल किया और अब उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखकर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। कीर्ति का कहना है कि योगी सरकार की इस पहल ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऋण के लिए भी आवेदन किया है, जिससे वे अपने इस व्यवसाय को और विस्तार देना चाहतीं हैं। कीर्ति का यह सफर बताता है कि जब सरकार की योजनाएं सही हाथों तक पहुंचतीं हैं और उनमें मेहनत व संकल्प जुड़ जाता है, तो बदलाव निश्चित होता है। आज वह न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहीं हैं।

नवजात शिशु का शव गेहूं के खेत में मिला, जांच में जुटी पुलिस

औरैया। जिले के फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव भौनकपुर में बुधवार को गेंहू के खेत में एक नवजात शिशु का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में चर्चा का माहौल बन गया और मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। गांव के बाहर स्थित संदीप के खेत में इन दिनों गेंहू की फसल की कटाई चल रही है। शुक्रवार सुबह लगभग पांच बजे संदीप अपनी पत्नी निशा के साथ खेत में फसल काटने पहुंचे थे। जैसे ही वे खेत में आगे बढ़े उनकी नजर जमीन पर पड़े एक नवजात शिशु पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उन्होंने पाया कि शिशु मृत अवस्था में था और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। यह दृश्य देखकर दंपति घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फफूंद थाना प्रभारी अजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में शिशु मृत पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि एक नवजात शिशु का शव खेत में मिला है। पुलिस मामले की जांच की जा रही है।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष क्रम पर होगी निगाह

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के सत्र में शनिवार को यहां जब अपने घरेलू मैदान पर पहले मैच में आत्मविश्वास से ओतप्रोत मुंबई इंडियंस का सामना करेगा तो सभी की निगाहें उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर टिकी होगी। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल पारी की शुरुआत करने के लिए सात जोड़ियों को आजमाया था।

उम्मीद की जा रही थी कि इस साल वह इसमें अधिक स्थिरता लाएगा लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि समस्या अब भी बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 142 रन का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया था। केएल राहुल पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि नितीश राणा और पथुम निस्संका भी नहीं टिक पाए जिससे उसका स्कोर चार विकेट पर 26 रन हो गया। इसके बाद 22 वर्षीय समीर रिजवी ने 'इंपैक्ट प्लेयर' के रूप में उतरकर संयम और परिपक्वता का शानदार परिचय देते हुए नाबाद अर्धशतक लगाया। इन्होंने अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 119 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई थी। रिजवी का प्रदर्शन दिल्ली के लिए अच्छा संकेत है लेकिन शीर्ष क्रम में उसकी कमजोरी चिंता का विषय है। अब उसे जसप्रीत बुमराह के अगुवाई वाले मुंबई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना है और उसके लिए यह आसान नहीं होगा। अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में जुटी कैपिटल्स की टीम शीर्ष क्रम में अधिक स्थिरता देखने के लिए उत्सुक होगी। उसके पास दो विकल्प हैं। या तो पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने अभिषेक पोरेल या फिर निरंतरता बनाए रखने में नाकाम रहे पृथ्वी साव पर भरोसा दिखाए। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की अनुपस्थिति में भी कैपिटल्स की गेंदबाजी इकाई कहीं अधिक आश्वस्त दिखी। स्टार्क इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने धीमी गेंदों का चतुराई से इस्तेमाल करना जारी रखा है और चोट के कारण काफी समय तक मैदान से बाहर रहे टी नटराजन ने लखनऊ के खिलाफ तीन विकेट लेकर अपना योगदान दिया, जबकि मुकेश कुमार ने किफायती गेंदबाजी की।

कुलदीप यादव और कप्तान अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, जिससे विरोधी टीम को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दिल्ली की गेंदबाजों का सामना अब रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों से होगा और इसलिए उन्हें अपनी गति में विविधता और स्पिन पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। मुंबई इंडियंस पिछले कई वर्षों से आईपीएल में अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहा था लेकिन इस बार उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल करने पहले मैच में हार के 14 साल के सिलसिले को खत्म कर दिया जससे वह अधिक आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगा। रोहित ने 78 रन की तूफानी पारी खेलकर पुराने दिनों की याद दिला दी और टी20 क्रिकेट में शानदार वापसी की। उनके साथी सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने भी 81 रन की आक्रामक पारी खेलकर अच्छा सहयोग दिया। पूरी संभावना है कि वह टीम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे। उन्हें अनुभवी क्विंटन डीकॉक की जगह टीम में शामिल किया गया था।

मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने कसी गेंदबाजी की। सूर्यकुमार की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मुंबई ने पिछले मैच में उनका इंपैक्ट कलियर के रूप में इस्तेमाल किया और यह देखना बाकी है कि क्या भारतीय टी20 टीम का कप्तान शनिवार को फिरोज शाह कोटला में पूरी भूमिका निभाने के लिए फिट हैं या नहीं।

इस प्रकार हैं दोनों टीम

- **दिल्ली कैपिटल्स:** अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, टी नटराजन, माधव तिवारी, करुण नायर, साहिल पारख.
- **मुंबई इंडियंस:** हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।

मैच दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा।

वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में किया क्लीन स्वीप

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 9 विकेट से हराकर सीरीज पर क्लीन स्वीप कर लिया। यह मुकाबला बासेटेरे में गुरुवार (2 अप्रैल) को खेला गया, जहां लेग स्पिनर अलाना किंग के पांच विकेट ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में 49/1 का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन इसके बाद टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। 19वें ओवर तक स्कोर 78/5 हो गया।

ओपनिंग में 38 रन की साझेदारी के अलावा रीएलियाना ग्रिमोंड और चिनेल हेनरी के बीच 37 रन की साझेदारी ही कुछ हद तक टीम को संभाल सकी। ग्रिमोंड 27वें ओवर में किंग का शिकार बनीं, जिसके बाद पूरी टीम तेजी से सिमट गई। हेनरी ने 42 रन बनाकर नाबाद पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास समर्थन नहीं मिला और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 35.4 ओवर में 136 रन पर ऑलआउट हो गई। अलाना किंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर 5 विकेट झटके और मैच की सबसे बड़ी नायिका रहीं। उनके अलावा एशले गार्डनर ने भी 2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

137 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की। टीम ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़कर मैच पर पकड़ बना ली। जॉर्जिया वोल ही एकमात्र बल्लेबाज रहीं जो आउट हुईं। इसके बाद फोएबे लिचफील्ड और एलिस पेरी के बीच 87 रन की नाबाद साझेदारी हुई। लिचफील्ड ने 68 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि पेरी 33 रन बनाकर नाबाद रहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 19.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

रियाल मैड्रिड को रौंदकर बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में

बार्सिलोना। बार्सिलोना ने एक बार फिर दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए छह गोल दागकर अपने चिर प्रतिद्वंदी रियाल मैड्रिड को 6-0 से हराया और महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में लगातार आठवीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया।

बार्सिलोना ने क्वार्टर फाइनल का पहला चरण 6-2 से जीता था। इस तरह से उसने कुल मिलाकर 12-2 के बड़े अंतर से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीन बार की चैंपियन टीम बार्सिलोना की तरफ से दूसरे चरण में कैरोलिन ग्राहम हैनसेन ने दो गोल जबकि एलेक्सिया पुटेलस, इरेन पारेडेस, ईवा पजोर और एस्मी ब्रुग्ट्स ने एक-एक गोल किया। बार्सिलोना सेमीफाइनल में बायर्न म्यूनिख का सामना करेगा।

क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मुकाबले में ओलंपिक लियोनेस ने वोल्फ्सबर्ग को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई जहां उसका मुकाबला मौजूदा चैंपियन आर्सेनल से होगा। वोल्फ्सबर्ग पहले चरण के बाद 1-0 से आगे था। इस तरह से लियोनेस ने कुल 4-1 से जीत दर्ज की।

सूर्यवंशी के सामने होगी गुजरात के तेज गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा

अहमदाबाद। कैगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की मौजूदगी वाला तेज गेंदबाजी आक्रमण देखने में तो काफी खतरनाक लगता है, लेकिन शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मैच में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर 'वंडर ब्वाय' वैभव सूर्यवंशी के सामने उनकी कड़ी परीक्षा होगी।

पंद्रह वर्षीय सूर्यवंशी ने आईपीएल में अपने दूसरे सत्र की शानदार शुरुआत की। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केवल 15 गेंद पर अर्धशतक जड़ दिया था जिससे उसकी टीम ने 127 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर दिया था। सूर्यवंशी शनिवार को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में एक बार फिर से आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस का गेंदबाजी आक्रमण काफी मजबूत है जिसमें रबाडा, सिराज और प्रसिद्ध जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं। इस मैच में टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल से बेहतर रणनीति अपनाने की उम्मीद की जाएगी क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में टीम की हार के दौरान उनके कुछ फैसलों की आलोचना हुई थी। इस मैच में जहां सिराज को केवल दो ओवर दिए गए थे वहीं प्रसिद्ध को 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाया गया था।

बल्लेबाजी की बात करें तो नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जा रही है, जहां वे खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। टूर्नामेंट में अब तक सभी टीम ने लक्ष्य का पीछा करना अच्छा समझा है। राजस्थान रॉयल्स के पास नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर जैसे दो अच्छे तेज गेंदबाज हैं तथा वह गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर को शुरुआती ओवरों में कड़ी चुनौती देना चाहेंगे। गुजरात टाइटंस की समस्या उसकी शीर्ष तीन बल्लेबाजों की पर अत्यधिक निर्भरता है। कप्तान गिल (27 गेंदों में 39 रन) और बटलर (33 गेंदों में 38 रन) दोनों ही मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने रंग में नहीं दिखे। सुदर्शन (11 गेंदों में 13 रन) भी चोट से उबरने के बाद लय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया की मौजूदगी वाला उनका मध्य क्रम भी उतना भरोसेमंद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर टाइटन्स पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 220 रन बनाने होंगे ताकि उनके गेंदबाजों को सूर्यवंशी पर हावी होने का मौका मिल सके।

अगर वह लक्ष्य का पीछा करते हैं तो उन्हें विपक्षी टीम को 200 रन के अंदर रोकना होगा। पिछले दो सत्र में डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी कुछ खास प्रभावशाली नहीं रही। तेवतिया शुरुआत से ही आक्रामक नजर नहीं आए हैं। शाहरुख की अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के सामने तकनीकी दिक्कतें हैं और यह हैरानी की बात है कि आशीष नेहरा जैसे काबिल कोच ने उनका कोई अच्छा विकल्प नहीं ढूंढा है।

जहां तक रॉयल्स की बात है तो कागजों पर टीम काफी अच्छी दिखती है, हालांकि असम के रियान पराग को कप्तान नियुक्त करने के फैसले पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल जैसे भारतीय स्टार खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया।

इस प्रकार हैं दोनों टीम

- राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जड़ेजा, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा।
- गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बराड़, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, ल्यूक वुड, पृथ्वी राज यारा, टॉम बैंटन।

मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।

बजाज ऑटो की बिक्री मार्च में 20% बढ़कर 4,45,377 इकाई

नई दिल्ल। बजाज ऑटो लिमिटेड की मार्च में कुल बिक्री 20% बढ़कर 4,45,377 इकाई हो गई। मार्च 2025 में यह 3,69,823 इकाई थी। वाहन विनिर्माता कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मार्च में घरेलू बाजार में कुल बिक्री 2,66,290 इकाई रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 2,21,474 इकाई थी। घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री मार्च 2026 में 20% बढ़कर 2,21,021 इकाई हो गई जो मार्च 2025 में 1,83,659 इकाई थी। कंपनी ने बताया कि दोपहिया वाहनों का निर्यात भी 21% बढ़कर 1,59,452 इकाई हो गया जो पिछले वर्ष इसी महीने 1,32,073 इकाई था। वाणिज्यिक वाहन की कुल बिक्री मार्च में 20 प्रतिशत बढ़कर 64,904 इकाई रही जो मार्च 2025 में 54,091 इकाई थी। घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 45,269 इकाई रही जबकि मार्च 2025 में यह 37,815 इकाई थी।

भारत सरकार ने पेट्रोकेमिकल्स पर सीमा शुल्क किया माफ

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनैतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के ऊर्जा ढांचे को स्थिरता देने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं की हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीजल और एटीएफ पर हाल ही में पुनः लागू किए गए अप्रत्याशित निर्यात शुल्क रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी विशेष आर्थिक क्षेत्र आधारित रिफाइनरियों पर लागू नहीं होंगे।

यह निर्णय न्यायिक मिसालों के आधार पर लिया गया है, जिससे भारत के सबसे बड़े ईंधन निर्यातकों के लिए एक बड़ी अनिश्चितता समाप्त हो गई है। वर्तमान में सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर 21.50 रुपये और एटीएफ पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क फिर से लगाया है, लेकिन निर्यात-उन्मुख इकाइयों को इस बोझ से मुक्त रखा गया है। घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को लागत

- रिलायंस की एसईजेड रिफाइनरी को अप्रत्याशित निर्यात कर से मिली बड़ी राहत, ऊर्जा सुरक्षा के लिए उठाए कड़े कदम

के दबाव से बचाने के लिए सरकार ने चुनिंदा रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून, 2026 तक पूर्ण सीमा शुल्क छूट देने का ऐलान किया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक "लक्षित राहत" है।

वैश्विक व्यापार मार्गों, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता के कारण बढ़ती शिपिंग लागत और देरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने माना है कि इससे राजस्व की हानि हो सकती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के दौर में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और व्यापारिक बाधाओं की रीयल-टाइम निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालई समन्वय परिषद का गठन किया गया है।

वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में यह समिति रोजाना बैठक कर रही है ताकि निर्यातकों को रसद और कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी निर्यातकों के लिए ऋण अवधि बढ़ा दी है और शिपिंग लागत कम करने के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में एलपीजी और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ कमर्शियल गैस की आपूर्ति को भी प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जा रहा है।

पश्चिम एशिया संकट: सरकार ने इंडक्शन हीटर के उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर की चर्चा

नई दिल्ली। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच इंडक्शन हीटर व उससे जुड़े बर्तनों की बढ़ती मांग के मद्देनजर कंपनियों को इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों पर शुक्रवार को चर्चा की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस संकट ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया है। इससे खाना पकाने की गैस की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और लोग इंडक्शन हीटर और उसके अनुकूल बर्तन खरीद रहे हैं। बैठक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई। इसमें ऊर्जा सचिव, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एक अधिकारी ने कहा, " हमने चर्चा की कि इंडक्शन हीटर और उससे जुड़े बर्तनों (जैसे इंडक्शन कुकर के बर्तन) का उत्पादन किस तरह तेजी से बढ़ाया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और बाजार में ये तेजी से बिक रहे हैं। उद्योग जगत के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण खाना पकाने की गैस की आपूर्ति संबंधी चिंताओं के मद्देनजर इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक केतली की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, सरकार ने बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण पेट्रोरसायन उत्पादों के आयात को 30 जून तक तीन महीने के लिए सीमा शुल्क से छूट दी। इससे दवा, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों को राहत मिली तथा पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित हुई। हालांकि इस कदम से सरकारी खजाने पर 1800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान जहाज मार्गों में व्यवधान से उर्वरक, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत उर्वरक और पेट्रोलियम का एक प्रमुख आयातक देश है। अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले शुरू करने और तेहरान की व्यापक जवाबी कार्रवाई से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सेल ने 2025-26 में बिक्री, उत्पादन में बनाये नये रिकॉर्ड

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिक्री और उत्पादन दोनों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 201.4 लाख टन की अब तब की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की जो एक साल पहले के 180.7 लाख टन की तुलना में 11.5 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष के दौरान सेल ने भारतीय रेलवे को 12.5 लाख टन की रिकॉर्ड आपूर्ति की और अपनी यूनिवर्सल रेल मिल से अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जो कंपनी की कार्यकुशलता और देश के रेल नेटवर्क को बढ़ाने में उसके रणनीतिक योगदान को दिखाता है। कंपनी के निर्यात में भी 162 प्रतिशत की भारी बढ़त देखी गई, जो 2.9 लाख टन तक पहुंच गया है। सेल ने अब भूटान समेत नये विदेशी बाजारों में भी अपना विस्तार किया है।

RBI की MPC बैठक में ब्याज दरों पर होगा अहम फैसला

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की महत्वपूर्ण बैठक अगले सप्ताह 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच होने जा रही है। बाजार विशेषज्ञों और एचएसबीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों यानी रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव करने की संभावना कम है। हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता ने नीति निर्माताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जब तक ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर स्थिर नहीं हो जातीं, तब तक आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर ईएमआई का बोझ

बढ़ाने से बचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा ऊर्जा संकट पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक जटिल है, क्योंकि इस बार केवल कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में भी भारी बाधाएं देखी जा रही हैं।

यदि तेल की औसत कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा और महंगाई दर आरबीआई के 6 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर के भीतर बनी रहेगी। एचएसबीसी के मॉडल के अनुसार, रुपये की विनिमय दर को बचाने के लिए ब्याज दरों में जल्दबाजी में की गई बढ़ोतरी आर्थिक विकास की गति को धीमा कर सकती है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास दर को बचाए रखना होगा। आरबीआई ने हाल ही में 27 मार्च को बैंकों के विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़े नियमों को सख्त किया है, जिससे बाजार में अटकलें तेज हो गई थीं कि क्या दरों में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, नीति निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल मांग को नियंत्रित करने के बजाय आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दें।

यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो 'स्टिकी इन्फ्लेशन' (जिद्दी महंगाई) की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे भविष्य में दरों में वृद्धि अनिवार्य हो जाएगी। फिलहाल, सभी की निगाहें 8 अप्रैल को होने वाले आरबीआई के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि आपकी होम लोन और कार लोन की किस्तें स्थिर रहेंगी या बढ़ेंगी।

एनसीएल ने 2025-26 में रिकॉर्ड 13.7 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की इकाई एनसीएल ने शुक्रवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली और अन्य क्षेत्रों के अपने ग्राहकों को रिकॉर्ड 13.7 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है।

कंपनी ने कहा कि कुल कोयला प्रेषण में लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बिजली संयंत्रों को भेजा गया। एनसीएलने एक बयान में कहा, "बदलते वैश्विक ऊर्जा हालात और देश में बिजली की बढ़ती मांग के बीच, एनसीएल के निरंतर प्रदर्शन ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में अपना योगदान देते हुए एनसीएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली क्षेत्र और अन्य उपभोक्ताओं को 13.7 करोड़ टन कोयला भेजा है।" कंपनी ने 85.51 प्रतिशत कोयला पर्यावरण-अनुकूल माध्यमों से भेजा। एनसीएल ने 2025-26 में 14.05 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.08 प्रतिशत अधिक है।

एनसीएल ने कहा कि समीक्षाधीन वर्ष में उसने अपना वार्षिक उत्पादन लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उसकी जयंत परियोजना ने तीन करोड़ टन के साथ सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया जबकि दुधिचुआ और निगाही परियोजनाओं ने अलग-अलग 2.5 करोड़ टन का उत्पादन किया।

लीसा मिश्रा

ने 2022 में छह महीने तक आवाज़ खोने के बारे में किया खुलासा

मुंबई। गायिका और अभिनेत्री लीसा मिश्रा ने हाल ही में अपने जीवन का एक बेहद निजी अनुभव साझा किया, जिसे आमतौर पर लोग एक सफल और लगातार परफॉर्म करने वाले कलाकार से जोड़कर नहीं देखते। लीसा मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में उनकी आवाज़ लगभग छह महीने के लिए पूरी तरह चली गई थी। इसका कारण वोकल नोड्यूल्स थे, जो ज़्यादा इस्तेमाल और दबाव के कारण वोकल कॉर्ड्स पर बनने वाले छोटे-छोटे कठोर उभार होते हैं। लीसा इस समय को अपने करियर का सबसे कठिन दौर मानती हैं। एक पेशेवर गायिका के लिए आवाज़ सिर्फ एक साधन नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान, रोज़गार और भावनात्मक सहारा भी होती है। इसे खो देना न सिर्फ करियर के लिए बड़ा झटका होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत भारी पड़ता है। लीसा ने बताया कि यह अनुभव उनके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि इस दौरान उन्हें डर, आत्म-संदेह और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। हाल ही में लीसा ने लगातार चार दिनों तक कई शो किए, और इस दौरान उनकी आवाज़ पूरी तरह ठीक रही, बिना किसी परेशानी के। उनके लिए यह सिर्फ सफल परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि उस कठिन दौर से बाहर आने की एक बड़ी जीत है। अपने अनुभव को साझा करते हुए लीसा ने कहा कि 2022 में वोकल स्ट्रेन की वजह से उनकी आवाज़ छह महीने तक पूरी तरह चली गई थी, जो उनके लिए बेहद दर्दनाक अनुभव था। एक गायिका के लिए आवाज़ ही सब कुछ होती है आत्मविश्वास, करियर और पहचान। कई बार उन्हें लगा कि शायद वे फिर कभी पहले की तरह गा नहीं पाएंगी। जब भी वे गाने की कोशिश करतीं, तो आवाज़ की जगह सिर्फ हल्की-सी हवा निकलती थी। लेकिन अब लगातार कई शो करने के बाद उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही है, खासकर तकनीक में बदलाव के बाद।उन्होंने बताया कि इस दौर ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और अपने काम के प्रति सम्मान सिखाया। आवाज़ एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की बातचीत में भी करते हैं, इसलिए जब इसमें समस्या आती है तो ठीक होने के लिए बोलना, फुसफुसाना या गुनगुनाना भी बंद करना पड़ता है।

लीसा ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि एक प्रोफेशनल सिंगर होना सिर्फ मंच की चमक और तालियों तक सीमित नहीं है।

'रामायण' का टीजर पहुंचा लॉस एंजिल्स

नमित मल्होत्रा ने दी प्रतिक्रिया

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का पहला टीजर 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जारी किया गया। टीजर में रणबीर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम' के रूप में पहली बार दिखाया गया, जिसे लेकर दर्शकों में उत्साह देखा गया। हालांकि, भारत से पहले लॉस एंजिल्स में टीजर लॉन्च किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि टीजर को पहले लॉस एंजिल्स में दिखाने का उद्देश्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, बल्कि वैश्विक दर्शकों तक रामायण की कहानी पहुंचाना था। उन्होंने कहा, ₹दुनिया एक है, एक ही रामायण है और एक ही राम हैं। गौरतलब है कि टीजर की विशेष स्क्रीनिंग लॉस एंजिल्स के आईमैक्स थिएटर में आयोजित की गई थी। टीजर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने नाराजगी जताई और इसे भारतीय दर्शकों की अनदेखी बताया। वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म की अंतरराष्ट्रीय रणनीति पर भी सवाल उठाए। हालांकि, निर्माता ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य इस महाकाव्य को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। यह फिल्म दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

64 वर्ष की हुई जया प्रदा

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा शुक्रवार को 64 वर्ष की हो गई। जया प्रदा का मूल नाम ललिता रानी है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंदरी में 03 अप्रेल 1962 को एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्णा तेलुगु फिल्मों के वितरक थे। बचपन से ही जयाप्रदा का रूझान नृत्य की ओर था। उनकी मां नीलावनी ने नृत्य के प्रति उनके बढ़ते रूझान को देख लिया और उन्हें नृत्य सीखने के लिए दाखिला दिला दिया। चौदह वर्ष की उम्र में जयाप्रदा को अपने स्कूल में नृत्य कार्यक्रम पेश करने का मौका मिला। जिसे देखकर एक फिल्म निर्देशक उनसे काफी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म भूमिकोसम में उनसे नृत्य करने की पेशकश की लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में अपने माता-पिता के जोर देने पर जयाप्रदा ने फिल्म में नृत्य करना स्वीकार कर लिया।इस फिल्म के लिए जयाप्रदा को पारश्रमिक के रूप में महज 10 रुपए प्राप्त हुए लेकिन उनके तीन मिनट के नृत्य को देखकर दक्षिण भारत के कई फिल्म निर्माता -निर्देशक काफी प्रभावित हुये और उनसे अपनी फिल्मों में काम करने की पेशकश की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वर्ष 1976 जयाप्रदा के सिने करियर का महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उन्होंने के. बालचंद्रन की अंथुलेनी कथा के. विश्वनाथ की श्री श्री मुभा और वृहत पैमाने पर बनी एक धार्मिक फिल्म सीता कल्याणम में सीता की भूमिका निभाई। इन फिल्मों की सफलता के बाद जयाप्रदा दक्षिण भारत में अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई।वर्ष 1977 में जयाप्रदा के सिने कैरियर की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आदावी रामाडु प्रदर्शित हुई। जिसने टिकट खिड़की पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता एन.टी. रामाराव के साथ काम किया और शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचीं।